विषय सूची

महंगाई के खिलाफ संघर्ष रैली
रिपोर्ट.................................... 5

संसद में बहस

माओवाद के खिलाफ लड़ाई
अरुण जेटली........................ 20
प्रकाश जावडेकर.................. 21
यशवंत सिन्हा....................... 21

साक्षात्कार
डा. रमन सिंह....................... 24

लेख
बढ़ती आबादी और घटता बजट
प्रभात झा...................... 19

अन्य
जम्मू–कश्मीर कार्यकारिणी बैठक. 9
भाजपा अध्यक्ष का चेन्नई प्रवास. 10

सम्पादक
प्रभात झा सांसद
सम्पादक मंडल
सत्यपाल
के. के. शर्मा
संजीव कुमार सिन्हा
पृष्ठ संयोजन
धर्मेन्द्र कौशल
विकास सैनी
सम्पर्क
डा. मुकर्जी स्मृति न्यास
पीपी–66, सुब्रह्मण्यम भारती मार्ग
नई दिल्ली–110003
फोन नं. +91(11)–23381428
फैक्स : +91(11)–23387887
सदस्यता हेतु : +91(11)–23005700
सदस्यता शुल्क
वार्षिक 100रु. | त्रिवार्षिक 250रु.
e-mail address
kamalsandesh@yahoo.co.in

प्रकाशक एवं मुद्रक : डा. नन्दकिशोर गर्ग द्वारा डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, के लिए एक्सेलप्रिंट, सी–36, एफ.एफ. कॉम्पलेक्स, झण्डेवालान, नई दिल्ली–55 से मुद्रित करा के, डा. मुकर्जी स्मृति न्यास, पी.पी–66, सुब्रमण्यम भारती मार्ग, नई दिल्ली–110003 से प्रकाशित किया गया। : सम्पादक – प्रभात झा

> ''खाली हाथ आये और खाली हाथ चले। जो आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा।''
>
> –श्रीमद्भगवद्गीता

सम्पादकीय

जनता ने चेताया कांग्रेस को, अब नहीं सहेंगे...

कांग्रेस–नीत यूपीए सरकार कहे या न कहे लेकिन उन पर जो बीत रही होगी, वह किसी और पर नहीं बीत रही होगी। कांग्रेस ने देश की जनता को महंगाई की मार दी। वहीं 21 अप्रैल को दिल्ली की सड़कों पर भाजपा के आह्वान पर देश उतर आया। प्रदर्शन और रैली के पिछले रिकार्ड वैसे ही टूट गए, जैसे इस बार की गर्मी वर्षों का रिकार्ड तोड़ रही हैं। महंगाई से पीड़ित परिवारों के हिल चुके चूल्हे चौकों की चीत्कारों से संसद में बैठी सत्ता की कुर्सी डोल गई। यह मात्र भाजपा या विपक्ष के तेवर नहीं थे, बल्कि जनता के तेवर थे।

कांग्रेस ने विश्वासघात की इंतहा कर दी। सौ दिन में महंगाई पर नियंत्रण का वादा कर जनता से वोट बटोरने वाली कांग्रेस ने अपने ही हाथों अपने मुंह पर कालिख पोत ली। महंगाई कम करना तो दूर, नियंत्रण रखना भी कठिन हो गया। उल्टे सभी जरूरत वाली चीजों की, जिससे घर की रसोई चलती है, के भाव चौगुने हो गए। निर्दयी कांग्रेस की सरकार उल्टे दादागिरी से यह कह रही है कि अभी महंगाई कम नहीं होगी। संसद में भाजपा ही नहीं समूचे विपक्ष ने एक स्वर में यूपीए की कहर ढाती महंगाई के विरूद्ध शंखनाद किया। बहस की। पर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। बजट प्रस्तुत किया। ढाक के तीन पात। जन आक्रोश की ऐसी अवहेलना आजादी के बाद कभी देखने को नहीं मिली।

इसी बीच भारतीय जनता पार्टी की इंदौर में संपन्न राष्ट्रीय कार्यपरिषद की बैठक भाजपा अध्यक्ष नितिन गडकरीजी ने देशभर से कार्यकर्ताओं का आह्वान किया कि ''चलो दिल्ली'' और संसद को घेरो''। देशभर से आए कार्यकर्ताओं ने पुरजोर समर्थन किया। कार्यकर्ताओं ने देशभर में अलख जगाया। सच्चाई सामने लाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिनजी ने प्रधानमंत्री से 14 सवाल पूछे। महाघोटाला का पर्दाफाश किया। देश में सड़कों पर संघर्ष का माहौल बना। भाजपा महंगाई के मुद्दे को गांव–गांव तक ले गई। देश का चौपाल स्वयं यूपीए सरकार की कहर ढा रही महंगाई की चर्चा का केन्द्र बन गया। माहौल ऐसा

बना कि जनता ने 21 अप्रैल को भारत की राजधानी की सड़कों पर महंगाई से त्रस्त दास्तान को जन सैलाब के रूप में जनआक्रोश को व्यक्त किया।

'संसद चलो' यह सड़क का नारा है। इस समय कोई चुनाव नहीं है। भाजपा ने जनता के दर्द को जुबां दी है। भाजपा ने जनपीड़ा का बीड़ा उठाया है। भाजपा की यह पहल सड़कों के संघर्ष की शुरूआत है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की जनता को मूर्ख बनाने के अर्थशास्त्र की पोल खुल गई। लोगों को मूर्ख बनाने का लाभ अधिक दिन नहीं चलता। भाजपा ने जन–नब्ज पर हाथ रखा है।

दिल्ली की सड़कों पर उमड़ा जनसैलाब अब जब अपने–अपने इलाके में लौटेंगे तो वहां पर भी संघर्ष जारी रखना होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का यह कहना कि अब हमें सड़कों पर संघर्ष करना है, ''यह भाजपा की नहीं देश की पीड़ा है।'' गांवों और शहरों में जो जनसमस्याएं है, भाजपा कार्यकर्ताओं को उनके लिए स्थानीय स्तर पर जनसंघर्ष शुरू करना होगा।

देश की राजधानी ने भाजपा की शक्ति देखी। भाजपा ने स्वयं अपनी मेहनत को देखा। देश राजनेताओं और राजनैतिक दलों से सच्ची लड़ाई की उम्मीद रखती है। पिछले कुछ वर्षों में 'संघर्ष' से लोग दूर हुए थे। इस सच्चाई से तो कोई नकार नहीं सकता कि 'संघर्ष' यदि परिणामकारी हो तो जनता स्वतः खड़ी हो जाती है। भाजपा ने महंगाई को लेकर यूपीए सरकार को जो जन–जन की पीड़ा वाला आईना दिखाया उसमें कांग्रेस–नीत यूपीए को अपनी ही सूरत बदसूरत दिखने लगी है। भाजपा बधाई की पात्र है। सड़कों के संघर्ष के परिणाम में देर भले ही हो, पर अंधेर नहीं होगा। ■

दिल्ली महारैली के लिए कार्यकर्ताओं का अभिनन्दन

आप सभी के सहयोग से सफल हुई रैली - नितिन गडकरी

नई दिल्ली की विशाल रैली में 21 अप्रैल को भारी जनसमूह ने सरकार द्वारा महंगाई न रोक पाने के लिए भीषण प्रदर्शन किया। इस आयोजन पर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने के लिए देश के कोने–कोने से आये भाजपा कार्यकर्ताओं को बधाई दी।

उन्होंने कहा कि पिछले दो महीने से भी अधिक समय से भाजपा के कार्यकर्ताओं ने ग्राम स्तर तक अपना अथक अभियान चलाकर इस ऐतिहासिक रैली में लोगों को एकत्र कर इस रैली को सफल बनाया है।

इस अवसर पर मैं अपने सभी राष्ट्रीय पदाधिकारियों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों, प्रदेश अध्यक्षों, भाजपा शासित मुख्यमंत्रियों, उप–मुख्यमंत्रियों, राज्य मंत्रियों, सांसदों, विधायकों, विधान–परिषद सदस्यों, सभी मोर्चों, राज्य–कार्यकारिणी सदस्यों, पार्षदों, जिला अध्यक्षों, जिला कार्यकारिणी सदस्यों, मण्डल अध्यक्षों, मण्डल कार्यकारिणी सदस्यों, जिला परिषद सदस्यों, नगरपालिका सदस्यों, सरपंचों और विभिन्न स्तरों पर पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हार्दिक अभिनन्दन करता हूं। इस ऐतिहासिक सफलता के लिए मैं अपने सभी पार्टी जनों का नमन करता हूं।

मैं इस अवसर पर मीडिया के सभी बंधुओं को भी उनके सक्रिय सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं।

मैं दिल्ली की सभी सरकारी एजेंसियों के प्रति भी अपना आभार प्रगट करता हूं।

और अंत में, मैं भाजपा की ओर से दिल्ली, एनसीआर और पड़ोसी राज्यों के वासियों से रैली के दौरान यातायात जाम के कारण हुई असुविधा के लिए व्यक्तिशः क्षमायाचना करता हूं। ■

संसद से सड़क तक संघर्ष जारी रहेगा

केन्द्र की गलत आर्थिक नीतियों और कुशासन के चलते महंगाई बढ़ी : नितिन गडकरी

Xत 21 अप्रैल, 2010 को यूपीए सरकार की गलत नीतियों से बेलगाम हुई महंगाई के विरोध में भाजपा के आह्वान पर देश के कोने–कोने से आए लाखों लोगों ने संसद पर दस्तक दिया और कांग्रेसनीत केन्द्र सरकार को चेतावनी दी कि 'महंगाई रोक दो–वरना गद्दी छोड़ दो'।

महंगाई से आम आदमी किस कदर परेशान हैं इसकी बानगी रामलीला मैदान में स्वतः ही दृश्यमान हो रही थी। वर्षों बाद लोगों का सैलाब इस कदर उमड़ा कि यह मैदान छोटा पड़ गया। जितने लोग रामलीला मैदान में थे उतने ही लोग दिल्ली की सड़कों पर। भारत की राजधानी महंगाई विरोधी नारों से गूंज उठी। महंगाई के विरोध में रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ। इसके पश्चात् लाखों प्रदर्शनकारियों ने एक हाथ में भाजपा का झंडा तो दूसरे हाथ में तख्ती लिए संसद की ओर मार्च किया। तख्तियों पर– 'सोनिया–मनमोहन की जोड़ी, आम आदमी की कमर तोड़ी', 'सोनिया का देखो खेल, महंगी चीनी महंगा तेल', 'कांग्रेस का हाथ, जमाखोरों के साथ', 'जबसे कांग्रेस आई है, कमरतोड़ महंगाई है', 'घेरो संसद बांधो दाम, महंगाई पर कसो लगाम', आदि महंगाई विरोधी नारे लिखे हुए थे। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने रंजीत फ्लाई ओवर के सामने रोक दिया। लेकिन हजारों लोग जंतर–मंतर तक पहुंचने में सफल हो गए, जहां एक सभा के बाद महारैली समाप्त हो गई।

जनसभा को संबोधित करते हुए Hkktik d jk"Vªh; vè;{k Jh fufru xMdjh ने संप्रग सरकार को गांव, गरीब और मजदूर विरोधी सरकार करार दिया। उन्होंने कहा कि 'गरीबी हटाओ' के नाम पर कांग्रेस सरकार गरीबों को हटाने पर तुली हुई है। इस सरकार के शासन में भ्रष्टाचार चरम पर है। दाल, चावल और चीनी का घोटाला हुआ। गोदामों में अनाज सड़ रहा है। आम आदमी दाने–दाने को मोहताज है। किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हैं। बड़ी संख्या में युवा बेरोजगार हो रहे हैं। इस सरकार ने गरीब आदमी के पेट पर लात मारी है, हमें इसके खिलाफ लड़ना है।

उन्होंने कहा कि महंगाई को कम करने के लिए केन्द्र सरकार गंभीर नहीं है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम Double digit growth rate की तरफ जा रहे हैं। कमलनाथ कहते हैं कि गरीब लोग ज्यादा खाते हैं। चिदम्बरम ने कहा कि हमने कुत्तों के खाने वाली बिस्किट पर टैक्स माफ कर दिया है। प्रणब कहते हैं कि चिंता की कोई बात नहीं। शरद पवार का कहना है कि चीनी, गेहूं, चावल की कीमतें अमेरिका और इंग्लैंड की तुलना में भारत में सस्ती है। सोनिया गांधी कहती हैं कि खाद्य पदार्थों की महंगाई के बारे में कांग्रेस सरकार को पत्र लिखेंगी। श्री गडकरी ने कहा कि यूपीए सरकार ने दावा किया था कि 100 दिनों के अंदर महंगाई कम हो जाएगी। लेकिन अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली कांग्रेस शासन में महंगाई बढ़ती ही जा रही है। सरकार की नीयत में खोट है। देश में बढ़ रही महंगाई के लिए यूपीए की गलत आर्थिक नीति और कुशासन जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि हमने हाल में

महंगाई को लेकर चार्जशीट जारी की और प्रधानमंत्रीजी से 14 सवाल पूछे लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। मैं विश्वास से कह सकता हूं कांग्रेस का कोई माई का लाल इन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। यदि उनमें हिम्मत है तो वे हमसे मीडिया में खुली बहस करे। उन्होंने आंकडों का हवाला देकर संप्रग सरकार की पोल खोलते हुए कहा कि विश्व में चीनी 28 रूपए किलो है जबकि भारत में 38 रूपए किलो, ऐसा क्यों?48 लाख टन चीनी का निर्यात 12.50 रूपए से किया गया और उसे 22 रूपए की दर से आयात किया गया। अभी भी देश में 42 करोड़ लोगों से भी ज्यादा गरीबी रेखा के नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं। मेरे पास 25 देशों की महंगाई के आंकड़े हैं। इन देशों में मुद्रास्फीति की दर दो प्रतिशत है जबकि भारत में यह 11 प्रतिशत है।

श्री गडकरी ने उत्तर प्रदेश की बसपा सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि करोडों रूपए पुतले के लिए खर्च किए जा रहे हैं लेकिन किसानों के हितों की रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किए जा रहे हैं।

झलकियां

- रामलीला मैदान में लाखों की मौजूदगी में राजस्थान के मेवाड़, मेवात, मारवाड़, हाड़ौती ओर शेखावटी की पगड़िया पहने पुरूष एवं घाघरा–लूगड़ी पहने राजस्थानी महिलाओं का एक जत्था पूरी रैली के आकर्षण के केन्द्र बने हुए थे।
- कई लोग कई किस्म की वेशभूषा बनाए हुए थे, कोई सब्जी की माला पहने था, तो कोई शरीर पर पोस्टर चिपकाए घूम रहा था।
- चिलचिलाती गर्मी में भी लोग जमकर नारे लगा रहा थे। मंच से नारे लगते ही लोगों में जोश भर जाता। लोगों का उत्साह काबिले तारीफ था। चाहे वे ठंडे प्रदेश से आए हो या गरम प्रदेश से, सभी ने रैली में बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया।
- सुबह 8 बजे से ही रामलीला मैदान में जाने वाले कार्यकर्ताओं का तांता नहीं टूट रहा था। बस, छोटे वाहन से पहुंचने वाले लोगों का रेला जैसा नजारा दिखाई दे रहा था। सभी को प्रदर्शन स्थल पहुंचने की जल्दी थी। आईटीओ चौरोहे पर वाहन रोकने की स्थिति में कार्यकर्ता संसद मार्ग और रामलीला मैदान तक पैदल ही चलते रहे।
- पुरूष और महिला कार्यकर्ता ढोल–नगाड़ों के साथ माथे पर भाजपा का केसरिया झंडा बांधे खूब झूमे। वे गाना भी गा रहे थे कि बाकी जो कुछ बचा था उसे महंगाई मार गई।
- महिला कार्यकर्ताओं ने भी बढ़चढ़कर रैली में हिस्सा लिया। कोई कमल के फूलवाली साड़ी पहनकर आई थी तो किसी ने भाजपा के रंग का सलवार सूट पहन रखा था।
- भीषण गर्मी के बीच संपन्न हुई रैली में लोगों को गर्मी से बचाने के लिए बड़े पैमाने पर पानी का इंतजाम किया गया था। पानी की यह व्यवस्था सिर्फ रैली स्थल के आसपास ही नहीं; दिल्ली के बॉर्डरों पर भी की गई थी।

उन्होंने कहा कि देशवासियों को अब अटलजी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार की याद आने लगी है। उन दिनों लोग मेहमानों का सत्कार करने में जुट जाते थे तो वहीं आज कांग्रेस शासन में लोग कहते हैं कि आया मेहमान कब जाए कि हम खाना खाएं।

श्री गडकरी ने कहा कि महंगाई के विरूद्ध संघर्ष में आज जितने लोग यहां आए हैं उससे 10 गुना लोग दिल्ली की सड़कों पर खड़े हैं। महंगाई के प्रति जनता में बेहद आक्रोश व्याप्त है, आज की रैली ने यह सिद्ध कर दिया है।

Hkktik llnh; ny d vè;{k Jh ykyÑ".k vkMok.kh ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी को बधाई देते हुए कहा कि उनके नेतृत्व में दिल्ली में आयोजित यह पहली रैली असाधारण है। इसने पूर्व की सभी रैलियों को मात दे दी है। उन्होंने कहा कि महंगाई को लेकर यह सरकार पूरी तरह विफल हुई है। महंगाई जिस प्रकार से बढ़ी है उससे आम आदमी तो

त्रस्त हैं ही मध्यम श्रेणी के लोग भी परेशान हैं। गत 6 सालों से खाद्य पदार्थों की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। 100 प्रतिशत, 200 प्रतिशत और 250 प्रतिशत तक बढ़ीं। उन्होंने कहा कि कांग्रस शासन में महंगाई बढ़ने के दो प्रमुख कारण हैं, पहला– कुप्रबंधन और दूसरा– घोटालों के रूप में भ्रष्टाचार। वहीं भाजपा शासित राज्यों– मध्यप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखण्ड, कर्नाटक प्रगति कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि महंगाई के विरोध में इस संघर्ष में इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। यूपीए सरकार समझ ले कि यह संकट की चेतावनी है।

ioZ dsUnzh; ea=h Mk- eqjyh eukgj tks'kh ने कहा कि महंगाई के विरूद्ध यह महाकुंभ है। यह संघर्ष केवल रैली आयोजन तक नहीं, केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के विरूद्ध संघर्ष जारी रहेगा। डॉ. जोशी ने कहा कि महंगाई कांग्रेस के चरित्र में है। इंदिरा गांधी के समय में भी महंगाई बेलगाम रही जबकि जनता पार्टी और भाजपा नेतृत्व वाली सरकार के समय महंगाई नियंत्रित रही।

उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार आम आदमी के नाम पर सत्ता में आकर धनी लोगों के लिए काम करती है। यूपीए के मंत्रियों के पास महंगाई की तरफ ध्यान देने की फुर्सत नहीं है, उसके कृषि मंत्री व विदेश मंत्री क्रिकेट पर ज्यादा ध्यान देते हैं।

उन्होंने सरकार से सवाल करते हुए कहा कि उसने जनता को आश्वासन देने के अलावा क्या दिया है। सट्टाबाजार व जमाखोरों के कारण महंगाई बढ़ रही है। गरीबों की जेब काटकर सट्टाबाजार बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि जनता में सरकार की गलत नीतियों के प्रति आक्रोश है। यह अंगड़ाई मात्र है। आगे बड़ी लड़ाई है। इसके साथ ही उन्होंने यूपीए सरकार को चेताते हुए कहा कि जो सरकार देश के आम आदमी को बुनियादी सुविधाओं न उपलब्ध करा सके उसे एक मिनट भी सत्ता में रहने का अधिकार नहीं है।

Hkktik ds ioZ jk"Vªh; vè;{k Jh jktukFk flag ने कहा कि आज देश के कोने–कोने से लाखों लोग संसद पर दस्तक देने आए हैं और वे आवाज बुलंद कर रहे हैं कि या तो महंगाई कम करो या गद्दी छोड़ दो।

श्री सिंह ने कहा कि जब–जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार आई, तब–तब महंगाई बेतहाशा बढ़ी जबकि एनडीए शासन के दौरान महंगाई बंधी रही। गत 6 वर्षों से महंगाई बेलगाम है। क्या कारण है कांग्रेस के हुकूमत में महंगाई बढ़ने लगती है। सच तो यह है कि कांग्रेस सरकार के आर्थिक कुप्रबंधन के कारण महंगाई बढ़ रही है।

उन्होंने चिंता प्रकट करते हुए कहा कि यूपीए को सर्वाधिक चिंता आइपीएल की रहती है लेकिन वह देश की बुनियादी समस्याओं के बारे में चुप्पी साधे रहती है। गांव की गरीबी निरंतर बढ़ती जा रही है। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं वहीं अमीर और अमीर होते जा रहे हैं। 42 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे जीवन निर्वाह करने पर अभिशप्त हैं। लाखों टन गेहूं सरकार के गोदामों में सड़ रहा है। उचित कीमत पर न खाद्य मिल रहा है और न ही पानी, बिजली मिल पा रही है। लेकिन कांग्रेस सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंगती। उन्होंने कहा कि किसानों की माली हालात सुधारे बिना समृद्ध भारत का सपना साकार नहीं हो पाएगा। किसानों की क्रयक्षमता बढ़ानी होगी।

उन्होंने कहा कि सारे हिन्दुस्तान में हाहाकार मचा है। महंगाई से लड़ने की कुव्वत सिर्फ भाजपा में है। दिल्ली में दी गई यह दस्तक गांव–गांव तक पहुंचनी चाहिए।

ykdlHkk esa foi{k dh usrk Jherh lq"kek Lojkt ने कहा कि देश में बढ रही महंगाई को लेकर यूपीए सरकार ने तीन प्रमुख कारण गिनाए हैं। पहला, प्राकृतिक आपदा, दूसरा, किसानों को अधिक समर्थन

तीन आलू के कितने रूपए होंगे

श्री लालकृष्ण आडवाणी ने कहा कि महंगाई के हालात यह है कि अब सब्जी किलो–दो किलो के हिसाब से नहीं, नग के हिसाब से बिकने लगी है। अपनी बेटी का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बाजार में सब्जीवाले के पास एक खरीददार ने तीन आलू चुनकर पूछा कि ये कितने के मिलेंगे।

गोदामों में सड़ाया जा रहा अनाज

श्री राजनाथ सिंह ने आरोप लगाया कि एफसीआई के गोदामों में अनाज इसलिए सड़ाया जा रहा है ताकि कल को उन्हें अनुपयोगी बताते हुए कौड़ी के दाम में शराब बनाने वालों को बेच दिया जाए। हाल ही में हरियाणा के दौरे में उन्होंने पाया कि एफसीआई गोदामों व खुले आसमान के नीचे में दो से तीन साल पुराना अनाज सड़ रहा है, लेकिन बाजार में महंगाई बढ़ती जा रही है।

वेंकैया नायडू की तुकबंदियां

भाजपा के पूर्व अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू ने कई बातों को बहुत चुटीले अंदाज में तुकबंदियों में कहा, जैसे पीएम प्रीसाइड, मैडम डिसाइड्स या पीपुल्स वीपिंग, गवर्नमेंट स्लीपिंग या पीपुल्स वायलेंस बट सोनिया साइलेंस या फिर कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ को उन्होंने कहा कांग्रेस का हाथ, आम आदमी के साथ विश्वासघात और आम आदमी के लिए घोषणा, अमीरों के लिए पोषण।

मूल्य देना और तीसरा, आर्थिक मंदी। यह गलत है। वास्तव में सरकार की गलत नीतियों के कारण महंगाई बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि संप्रग शासन में दाल, चीनी और चावल के आयात–निर्यात में घोटाला हुआ। इसी महाघोटालों के विरोध में यह संघर्ष हैं। आज देश की जनता बेखबर सरकार को चेताने आई हैं। जनता के इस संघर्ष में भाजपा अग्रणी भूमिका निभाएगी।

उन्होंने रैली में उपस्थित विशाल जनसमूह से 'महंगाई रोक दो–वरना गद्दी छोड़ दो' का सामूहिक नारा उद्‌घोष कराया और कहा कि यह संघर्ष जो छिड़ा है आज केवल आगाज है। सरकार चेत जाए और जनता का दुख–दर्द दूर करे। यदि सरकार ने महंगाई खत्म नहीं की तो गद्दी छोड़वाकर रहेंगे।

jkT; lHkk esa foi{k ds usrk Jh v#.k tsVyh ने कहा कि जब भाजपा ने महंगाई के विरोध में 21 अप्रैल को विशाल रैली करने की घोषणा की, तो उस वक्त कई लोगों ने आशंकाएं व्यक्त की थी, लेकिन आज सबको यह स्पष्ट हो गया कि भाजपा संसद में भी जरूरी मुद्दों पर आवाज बुलंद करती है और सड़कों पर भी प्रबल संघर्ष करती है। श्री जेटली ने यूपीए सरकार को हर मोर्चे पर विफल करार देते हुए कहा कि यह सरकार आतंकवाद से लड़ने में नाकामयाब रही। माओवाद से लड़ने में अक्षम साबित हुई और महंगाई को कम करने के मोर्चे पर तो पूरी तरह से विफल हो गई। उन्होंने कहा कि आर्थिक मंदी से बाहर निकलने के बाद कीमतें कम हो जाती हैं लेकिन हिन्दुस्तान में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ गई। देश में रिकार्ड पैदावार हुई। सरकारी गोदामों में अनाज सड़ रहा है। किसानों को उचित दाम नहीं मिल रहा है। बजट में डीजल और पेट्रोल की कीमतें बढ़ा दीं। वहीं चीनी पर एक्साइज ड्यूटी

"मनमोहन सिंह के नेतृत्व में जब यूपीए की सरकार बनी तो लोगों को उम्मीद थी कि अब गरीबी हटेगी लेकिन हुआ उल्टा।"

& fufru xMdjh] jk"Vªh; v/;{k Hkktik

"आम आदमी और गरीब होता जा रहा है अटलजी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के वक्त से कीमतों में आज 100 से 250 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो गई है।"

& ykyÑ".k vkMok.kh] vè;{k Hkktik lalnh; ny

"सरकार की गलत नीतियों और घोटाले की वजह से महंगाई बढ़ रही है, न कि सरकार के बताए कारणों से"

& lq"kek Lojkt] usrk foi{k yksdlHkk

"पूरी दुनिया में पेट्रोल व डीजल सस्ते दर पर बेचे जा रहे हैं, लेकिन यहां सरकार 50 फीसदी टैक्स वसूल रही है"

& v#.k tsVyh] usrk izfri{k jkT;lHkk

"देश की जनता महंगाई से परेशान है, लेकिन देश के आला मंत्री आईपीएल (इंडियन प्रीमियम लीग) में व्यस्त हैं।"

& Mk- eqjyh euksgj tks'kh] iwoZ Hkktik vè;{k

"कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ विश्वासघात" अब यह साबित हो गया है। आम जनता यह जानना चाहती है कि बेतहाशा बढ़ती महंगाई पर कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी चुप क्यों है।

& ,e- oasd¦;k uk;Mw] iwoZ jk"Vªh; vè;{k Hkktik

"सरकारी गोदामों में लाखों टन अनाज खुले आसमान के नीचे रखा सड़ रहा है, लेकिन लोगों को उपयुक्त कीमत पर अनाज नहीं मिल रहा।"

& jktukFk flag] iwoZ jk"Vªh; vè;{k Hkktik

"महंगाई के खिलाफ भाजपा तीन महीने से आंदोलन चला रही है, हम यूपीए सरकार को उखाड़ कर ही दम लेंगे।"

& vuar dqekj] jk"Vªh; egklfpo Hkktik

"उद्योगपतियों की वजह से महंगाई बढ़ रही है। इसमा कारण राज्य सरकार नहीं है, बल्कि केन्द्र सरकार है।"

& lq'khy eksnh] mieq[;ea=h ¼fcgkj½

"महंगाई पर काबू पाने के लिए हमने केन्द्र सरकार को अनेक सुझाव दिए, लेकिन नजरअंदाज कर दिया।"

& f'kojkt flag pkSgku] eq[;ea=h ¼e-iz-½

"छत्तीसगढ़ 36 लाख लोगों को 2 रूपए प्रति किलो चावल दे सकती है तो केन्द्र सरकार क्यों नहीं"

&Mk- jeu flag] eq[;ea=h ¼NÙkhlx<½

"केन्द्र और दिल्ली की शीला सरकार की गलत नीतियों की वजह से महंगाई में आसमानी उछाल आया है।"

&çks- fot; dqekj eYgks=k] ¼fnYyh usrk foi{k½

"यूपीए सरकार गरीबों की दुहाई देकर सत्ता में आती है और गरीब लोगों का ही शोषण करती है।"

&çks- vk-ih- dksgyh] fnYyh izns'k Hkktik vè;{k

बढ़ा देना, यह सरकार की गलत नीतियां हैं। यदि ऐसे ही हालात रहे तो अगले 6 महीने में कीमतें और बढ़ेंगी।

इस रैली को भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वेंकैया नायडू, राष्ट्रीय महामंत्री श्री अनंत कुमार, भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रीगण श्री शिवराज सिंह चौहान (मध्यप्रदेश), डा. रमन सिंह (छत्तीसगढ़), प्रो. प्रेमकुमार धूमल (हिमाचल प्रदेश), श्री सुशील कुमार मोदी, (उपमुख्यमंत्री, बिहार) दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा एवं दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश कोहली ने भी जनसभा को संबोधित किया। भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री शांता कुमार, श्री कलराज मिश्र, श्रीमती करुणा शुक्ला, श्रीमती किरण घई, श्री मुख्तार अब्बास नकवी, श्री पुरुषोत्तम रूपाला, श्रीमती नज़मा हेपतुल्ला, श्री विनय कटियार, भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री श्री रामलाल, सह–संगठन मंत्री श्री व्ही. सतीष, श्री सौदान सिंह, भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव श्री थावरचंद गहलोत, श्रीमती वसुन्धराराजे, श्री रविशंकर प्रसाद, श्री धर्मेन्द्र प्रधान, श्री अर्जुन मुण्डा, श्री नरेन्द्र सिंह तोमर राष्ट्रीय सचिव श्रीमती किरण महेश्वरी, श्री वरुण गांधी, सुश्री सरोज पाण्डेय, श्रीमती स्मृति ईरानी, श्री किरीट सौमेय्या, सुश्री वाणी त्रिपाठी, श्री भूपेन्द्र सिंह, इसके अलावा अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता, लोकसभा में उपनेता श्री गोपीनाथ मुंडे, राज्यसभा में उपनेता श्री एस.एस. अहलूवालिया, राज्यसभा में मुख्य सचेतक श्रीमती माया सिंह, झारखण्ड के उपमुख्यमंत्री श्री रघुवरदास, कमल संदेश के सम्पादक श्री प्रभात झा, भाजपा केन्द्रीय कार्यालय प्रभारी श्री शाम जाजू, राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री प्रकाश जावडेकर, श्री शहनवाज हुसैन, श्री तरुण विजय, श्री रामनाथ कोविद, श्रीमती निर्मला सीता रमण आदि तथा उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री रमेश पोखरियाल 'निशंक' भी उपस्थित थे। सभा का संचालन राष्ट्रीय महासचिव श्री विजय गोयल ने किया। ■

यूपीए सरकार आतंकवाद की गलत नीतियों की शिकार : राजनाथ सिंह

गत 28 अप्रैल को जम्मू में भाजपा प्रदेश कार्यसमिति बैठक को संबोधित करते हुए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने यूपीए सरकार की दोषपूर्ण कूटनीति पर प्रहार करते हुए कहा कि भारत की आज तक की यह सबसे बड़ी असफलता है कि भारत का आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष करने में अमरीका या पाकिस्तान से कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। पिछले पांच–छह वर्षों से अमरीका और पाकिस्तान तालिबानी उग्रवादियों के खिलाफ मिलीभगत से काम में जुटे हुए हैं। परन्तु अमरीका ने आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत की कोई मदद नहीं की जबकि यह सभी जानते हैं कि भारत विश्व में सबसे अधिक प्रभावित देशों में आतंकवाद का शिकार बना रहा है। इसके विपरीत अमरीका से पाकिस्तान को मिल रही इमदाद ने भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों पर कोई रोक नहीं लगा पाई है।

पाकिस्तान की चालाक कूटनीति के कारण यूपीए सरकार की हाल की विशेष राजनयिक घटनाओं ने भारत के रणनीतिक हितों को नुकसान ही पहुंचाया है। प्रथम, अमरीका ने पाकिस्तान के साथ रणनीतिक भागीदार निभाने की इच्छा जताई है। द्वितीय, यूपीए सरकार बार–बार प्रयास करने के बाद भी अमरीकी आतंकवादी डेविड कोलमैन हेडली से पूछताछ करने की अनुमति भी प्राप्त नहीं कर पाई है।

स्वायत्तता इस बात के अलावा और कुछ नहीं है जिसे काश्मीरी अलगाववादियों ने जोरदार ढंग से हिमायत की है और ये अलगाववादी जम्मू–कश्मीर राज्य में पाकिस्तान के एजेण्डा को कार्यान्वित करने पर तुले हुए हैं। काश्मीरी अलगाववादी इस गुप्त कूटनीति की चाल चलते है और सरकार इन तत्वों के हाथों में आग से खेल ही नहीं रही है बल्कि वह भारतीय लोगों की भावनाओं को भी आहत कर रही है क्योंकि सरकार को यह मालूम होना चाहिए कि सरकार के पास ऐसा कोई जनादेश नहीं है, जो 1994 में पारित संसद के प्रस्ताव के खिलाफ जा सके, जिसमें साफ कहा है कि जम्मू और काश्मीर भारत का अभिन्न अंग है।

भाजपा को पाकिस्तान में बिगड़ती सुरक्षा स्थिति और साथ ही जम्मू और काश्मीर में घुसपैठ जारी रखने पर भी चिंता है। क्योंकि पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकवादियों की घुसपैठ रोक कर भारत की चिंता का समाधान करने में बुरी तरह से विफल रहा है, अतः भारत सरकार को पूरी नियंत्रण रेखा पर इसे रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए। यूपीए सरकार ने 2009–10 में जम्मू और काश्मीर के सीमा क्षेत्र से लगभग 37000 सैनिकों को हटा कर बहुत भारी गलती की है जिसके कारण हमारी सीमा पर घुसपैठ बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। सरकार को जम्मू और काश्मीर से सैनिक हटाने की अपनी नीति में गम्भीरता से संशोधन करना होगा और हमारे अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस उपाए करने होंगे। ■

२१वीं शताब्दी की राजनीति प्रगति और विकास की राजनीति होनी चाहिए : गडकरी

& laoknnkrk }kjk

भाजपा अध्यक्ष श्री गडकरी ने अपने चेन्नई दौरे के दौरान 10 अप्रैल को हिन्दू ग्रुप आफ पब्लिकेशंस के पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए मुद्रास्फीति, आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतें, इनके अगाऊ सौदे, महिला आरक्षण बिल और पार्टी पदों पर महिलाओं का एक–तिहाई कोटा, नक्सलवादियों की चुनौतियों, अयोध्या आदि अनेक विषयों पर बातचीत की। हम यहां 'हिन्दू' में 12 अगस्त को प्रकाशित टी. रामकृष्णन के लेख और बातचीत के प्रमुख अंशों का हिन्दी भावानुवाद प्रस्तुत कर रहे हैं:–

श्री गडकरी ने बताया कि हम महसूस करते हैं कि राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। यह हमारी अस्मिता से जुड़ा विषय है। हम इससे पीछे नहीं हटेंगे।

उन्होंने यह भी कहा कि मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से ही प्रेरणा मिलती रही है।

भाजपा के 52 वर्षीय अध्यक्ष श्री नितिन गडकरी ने यह भी कहा कि मुझे लगता है कि 21वीं शताब्दी की राजनीति प्रगति और विकास की राजनीति बननी चाहिए और मैं मानता हूं कि राजनीति तो सामाजिक–आर्थिक सुधारों का एक साधन है जिसके लिए 'सुशासन' पहली आवश्यकता है... हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन राज्यों में जहां हमारा शासन है वहां 'सुशासन' के द्वारा समाज के सभी क्षेत्रों में विकास की प्रक्रिया का विकास होता रहे। हमने इस पर काम शुरू कर दिया है। इस वर्ष हमारा लक्ष्य 10000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करना है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि यूपीए की गलत आर्थिक नीतियों और कुशासन से ही मुद्रास्फीति और आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कृषि तथा ग्रामीण भारत के प्रति उपेक्षा की भी आलोचना की।

भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि मेरी सर्वप्रथम प्राथमिकता यही है कि राजनीति सामाजिक–आर्थिक सुधारों का साधन बने। जब मैं विद्यार्थी था तो मैंने राजनीति में काम करने का फैसला किया और सोचा कि मैं देश, समाज और गरीबों के लिए कुछ कार्य कर सकूं। मैंने आजीवन इसी सिद्धांत पर कार्य किया है। सौभाग्य से, मेरे पास बुनियादी ढांचे के कार्य का अच्छा अनुभव रहा है। 1995–99 में महाराष्ट्र में लोकनिर्माण कार्य मंत्री के रूप में मुझे मुम्बई–पुणे एक्सप्रेसवे और मुम्बई में फ्लाईओवरों के निर्माण का अवसर मिला। वर्ली–बांद्रा सी–लिंक (जिसमें मुम्बई के पश्चिमी उपनगरों को शहर में जोड़ा गया) का कार्य भी मेरे समय में शुरू हुआ। मैंने 5 करोड़ ईक्विटी के साथ 8000 करोड़ रुपए का निर्माण कार्य किया था। मैं देश का प्रथम राजनीतिज्ञ बन पाया जिसने पूंजी बाजार से 4000 करोड़ रुपए इकट्ठा किए। मेरी सभी परियोजनाएं आर्थिक रूप से सफल रही। जब मैं विकास के बारे में सोचता हूं तो यह अनुभव मुझे मदद देता है।

मुझे लगता है कि उद्योग और कृषि महत्वपूर्ण है। औद्योगिक विकास के लिए हमें पानी, बिजली, परिवहन और संचार की आवश्यकता होती है। कृषि के लिए हमें बिजली, पानी, बीज और उर्वरक चाहिए। साथ ही, सिंचाई का भी महत्व है। दुर्भाग्य से, 1947 के बाद कृषि और ग्रामीण क्षेत्र की घोर उपेक्षा हुई। आज भी हमारे सामने खड़ी समस्याएं कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की उपेक्षा के कारण ही पैदा हुई हैं।

मंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद मैंने ग्रामीण क्षेत्रों पर कार्य शुरू किया। मैं न तो कार्पोरेट व्यक्ति हूं न ही उद्योगपति। मुझे बायो–डीजल, एथनाल,

बायो–फर्टिलाइजर्स, बायो–मेथेनाइजेशन, सौर ऊर्जा और विद्युत पर कार्य करने का गहरा लगाव है। मेरा चिंतन है कि लोगों की आस्था दो चीजों के प्रति रहती है– सरकार और ईश्वर! परन्तु यहां एक तीसरी चीज भी है– आप सामाजिक–आर्थिक जीवन के निर्माता हो सकते हैं। मैंने अपने भाजपा मित्रों और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मित्रों के साथ ''पूर्ति'' नाम का सहकारी भण्डार शुरू किया। अब इसकी बिक्री 35 करोड़ रुपए तक जा पहुंची है। सरकार के हस्तक्षेप के कारण हमने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी मॉडल का चुनाव किया। हमारे पास तीन चीनी मिलें हैं। हम बायोमास से बिजली पैदा करते हैं– गन्ने के सूखे चूरे से 24.5 मैगावाट और चावल के छिलके से 8 मैगावाट का उत्पादन होता है। मेरा सपना है कि हम कृषि की बिजली और ऊर्जा सैक्टर की तरफ मोड़ पाएं।

मेरा सपना है कि हरित ईंधन एथनाल और इसकी तकनीक के आधार पर पूरी तरह से ईंधन चलाए जा सकें। आजकल मैं इसी कार्य में व्यस्त हूं। बुनियादी रूप से मैं बायोफ्यूल पर काम कर रहा हूं। डिस्टिलरी के कारण हमारे पास बायोमेथेनाइजेशन संयंत्र हैं। हम गन्ने से बायोमास बना रहे हैं। प्रमुख उत्पादन बिजली है; इसके उप–उत्पाद चीनी, एथनाल और बायो–'फर्टिलाइजर्स हैं। मैं इनके विकास में बहुत रूचि रखता हूं।

मुझे लगता है कि 21वीं शताब्दी बहुत महत्वपूर्ण है और हम राष्ट्रवादी भावना और विचार रख कर इस शताब्दी में समाज के हर क्षेत्र में विकास और प्रगति कर सकते हैं। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जो समाज के हर क्षेत्र में विकास में जुटी हैं जिसमें वह विशेष रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर विशेष बल देती है।

सुशासन विकास के लिए प्रथम आवश्यकता है। हमारी पार्टी में एक सुशासन प्रकोष्ठ है और हमने गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर परिकर को प्रमुख नियुक्त किया है। पार्टी नौ राज्यों में शासन कर रही है। हमारी योजना है कि हम सभी सरकारों की योजनाओं का अध्ययन करें जिसमें वामपंथी और तमिलनाडु की सरकारें भी शामिल हैं। हम इस बात का अध्ययन कर रहे हैं कि किस प्रकार से हम उन सभी राज्यों में, जहां हमारा शासन है, वहां सुशासन के माध्यम से समाज के हर क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया को बढ़ा सकें।

दूसरी बात, अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने की है। हमने इसे शुरू कर दिया है। इस वर्ष हम 10000 कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखते हैं।

जहां तक तमिलनाडु के विकास की बात है, वहां पानी प्रमुख विषय है। नदियों को जोड़ने की परियोजना हमारे देश के लिए महत्वपूर्ण परियोजनाओं में शामिल है। कावेरी से आप को केवल 800 टीएमसी पानी मिलता है। परन्तु नदियों को जोड़ने से आपको 4000 टीएमसी पानी मिल सकता है। अब गुजरात को देखिए, वह भाजपा शासित राज्य है, वहां हमने 20 प्रतिशत पानी उपलब्धता में बढ़ोतरी की है। नर्मदा के कारण, गुजरात में कृषि विकास की दर 14 प्रतिशत हो गई है। भारतीय औसत ऋणात्मक 0.2 प्रतिशत है।

जहां तक पार्टी का सम्बंध है, हमारे पास अनेकों राजनैतिक योजनाएं हैं। व्यक्तिशः मैं महसूस करता हूं कि यूपीए की गलत आर्थिक नीतियों और कुशासन के कारण कीमतों में वृद्धि और मुद्रास्फीति हुई है। यह बात मैं ईमानदारी से महसूस करता हूं। मैं राजनीतिक रूप से यह बात नहीं कह रहा हूं।

जैसा कि आप जानते हैं कि हम दूसरे देशों को 12. 5 रुपए प्रति किलो चीनी का निर्यात करते हैं। डेढ़ वर्ष पूर्व सरकार ने निर्यात सब्सिडी और परिवहन सब्सिडी के रूप में 1.7 रुपए दिए। अब हम 28 रुपए से 35 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चीनी आयात करते हैं। हम विदेशों से लाल गेहूं 19 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीद रहे हैं। परन्तु सरकार किसानों को 9.5 रुपए दे रही हैं। आवश्यक वस्तुओं में 4,50,000 करोड़ रुपए की कुल बिक्री होती है परन्तु वितरण 4500 करोड़ रुपए का होता है। 99.24 प्रतिशत सट्टेबाजी और हेराफेरी में चला जाता है। 2004 में सरकार ने कमोडिटी एक्सचेंज में आवश्यक वस्तुओं को जोड़ दिया। इसका लाभ उठाने वालों में जालसाजी, सट्टेबाजों, बहुराष्ट्रीय कम्पनियां और कालाबाजारी करने वाले लोग ही तो हैं। किसानों को उचित कीमत नहीं मिल पाती हैं।

हरियाणा और पंजाब में, सरकार किसानों से 11.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदती है। आप देखेंगे कि एक महीने बाद खुदरा कीमतें 26 रुपए तक जा पहुंचेगी। सरकार सट्टेबाजी क्यों करने देती है? सरकार क्यों कमोडिटी एक्सचेंज में आवश्यक वस्तुएं जोड़ती हैं?

देश के कृषि क्षेत्र को कोल्ड स्टोरेज, प्री–कूलिंग प्लांट्स और गोदामों की जरूरत है। जहां तक मुझे जानकारी और आंकड़ों का पता है, हमारे पास अनाज रखने के लिए गोदामों की क्षमता मात्र एक–तिहाई है। सरकार ने कभी भी प्री–कूलिंग प्लांट्स, कोल्ड–स्टोरेज और कृषि–प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता नहीं दी।

'सिंचाई' राज्य सूची का विषय है। अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए मेरी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था; इसमें मैंने 60,000 करोड़ रुपए की योजना तैयार की थी। चार लेन

वाली राष्ट्रीय हाईवेज का मैं प्रमुख सलाहकार था। उस समय गांवों को जोड़ने का प्रश्न उठा था, जो एक राज्य–विषय था। मैंने वाजपेयी जी को बताया था कि गांवों को न जोड़ पाने के कारण ग्रामीण भारत के लोगों को अनेक वर्षों से अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन्होंने साहसिक निर्णय लिया कि प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का पूरा खर्च केन्द्र सरकार देगी और यह 60,000 करोड़ रुपए की योजना बनी।

हमें सिंचाई को समवर्ती सूची में जोड़ने की आवश्यकता है। आवश्यकता है कि जिसमें राज्यों और केन्द्र सरकार 50–50 प्रतिशत का अंशदान दें। इसमें सिंचाई की दुगुनी क्षमता बनेगी जिससे कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान होगा हमारा सचमुच जोर कृषि और ग्रामीण भारत के विकास पर होना चाहिए। हम अपने शासित राज्य–बिहार में भरपूर कोशिश कर रहे हैं जहां जीडीपी विकास दर ऋणात्मक 0.5 प्रतिशत थी वहां अब बिहार में यह 11 प्रतिशत है। सभी भाजपा शासित राज्यों में जीडीपी विकास दर में वृद्धि हुई है। आज हम इसे और भी बढ़ाने की योजना तैयार कर रहे हैं। अब हम इस बात में व्यस्त हैं कि किस प्रकार से रोजगार की संभावनाएं बढ़ें, किस प्रकार से गरीबी का उन्मूलन हो और किस प्रकार से और राज्यों में जीडीपी में वृद्धि हो और प्रति व्यक्ति आय बढ़े।

21वीं शताब्दी की राजनीति प्रगति और विकास की राजनीति होनी चाहिए। मुझे लगता है कि राजनीति सामाजिक–आर्थिक सुधार का साधन है। मैं अपने कैरियर के रूप में राजनीति का चुनाव नहीं कर रहा हूं। मैं भाजपा का कार्यकर्ता हूं और मुझे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के समय से प्रेरणा मिलती रही है। मैं देश और समाज के लिए कुछ करना चाहता हूं। मैं पार्टी का छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैंने अपना काम दीवारों पर पोस्टर चिपका कर और लिखने के कार्य से शुरू किया था। अब भी मैं वार्ड समिति स्तर पर काम करता हूं। यह सब कुछ भाजपा में ही सम्भव है कि मेरे जैसा छोटा सा कार्यकर्ता भी पार्टी के सर्वोत्तम पद अध्यक्ष तक पहुंच सकता है। दूसरी पार्टियों में यह बात सोची भी नहीं जा सकती। यहां तक कि मनमोहन सिंह भी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनने की बात सोच नहीं सकते। वह पद तो पारिवारिक रह गया है। निश्चित ही हमारी पार्टी और पार्टियों से अलग किस्म की पार्टी है।

क्या महिला आरक्षण बिल पर पार्टी में कोई पुनर्विचार हो रहा है?

बिल्कुल नहीं। जहां तक बिल के समर्थन का प्रश्न है, इसमें कोई समस्या नहीं है। जब बिल के लिए पार्टी की नीति की बात है तो हर व्यक्ति को मेरे साथ रहना होगा। हम किसी भी सांसद को पार्टी की नीति के खिलाफ कोई भूमिका निभाने नहीं देंगे।

परन्तु बहुत सी पार्टियों में कुछ रिजर्वेशन हैं। विशेष रूप से, राज्यसभा में मार्शलों द्वारा सदस्यों को निष्कासित करने से सभी पार्टियों के सदस्यों में बेचैनी है। यह लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। परन्तु जहां तक सिद्धांत की बात है, हमने बिल का समर्थन किया है। यह हमारा औपचारिक दृष्टिकोण है।

पार्टी पदों पर महिलाओं के लिए एक-तिहाई कोटा के कार्यान्वियन पर

पार्टी में 33 प्रतिशत महिला पदाधिकारी है। हमने महिलाओं को 33 प्रतिशत पद देने का निर्णय किया है। हमारे पास योग्य व्यक्ति है। हमारे पास अनेकों महिला कार्यकर्त्रियां हैं। उनका विशाल योगदान रहा है। हमें उन्हें उत्साहित करना है। हमने ऐसे लोगों को चुना है जो पार्टी का कार्य करने के लिए तैयार है।

खाद्य मुद्रास्फीति और बढ़ती कीमतों पर

हरियाणा और पंजाब में किसानों को 11–12 रुपए प्रति किलोग्राम मूल्य मिलता है। दो महीने पहले, खुदरा बाजार में कीमतें 24 से 26 रुपए प्रति किलोग्राम थीं। महाराष्ट्र में केवल गन्ने की कीमतें हमने 2000 रुपए प्रति टन दी हैं। तमिलनाडु में भी शायद यह कीमत 2000 रुपए प्रति टन है परन्तु अन्य आवश्यक वस्तुओं के मामले में जब किसान अनाज पैदा करता है, यह कीमत बहुत कम है। बाद में, खाद्यान्नों के अगाऊ सौदे और व्यापार से मूल्यों में वृद्धि होती है, परन्तु किसान को बहुत मामूली कीमत दी जाती है। साथ ही उपभोक्ताओं को दुगुनी कीमत चुकानी पड़ती है। सभी मामलों में यह बात 80 से 90 प्रतिशत खरी उतरती है।

मेरी पार्टी की राय है कि आवश्यक वस्तुओं में अगाऊ सौदे और व्यापार बंद होना चाहिए। (केन्द्रीय पेट्रोलियम मंत्री) मुरली देवड़ा ने कहा है कि कच्चे तेल के अगाऊ सौदों और व्यापार के कारण इस प्रकार के सौदों से कच्चे तेल की कीमतों से इस प्रकार वृद्धि होती है जिससे अनेक देशों के सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। इसलिए उन्होंने इसका विरोध किया। हमें इस बात का गहराई से अध्ययन करना होगा। यदि यह कमोडिटी एक्सचेंज, विशेष रूप से अगाऊ सौदे और व्यापार उन लोगों को लाभ पहुंचाते हैं जिनके पास पैसा है तो क्या यह समाज के लिए अच्छा है? इसी कारण सट्टेबाजी और हेराफेरी होती है जिससे आम आदमी–किसान, पत्रकार, अध्यापक, प्रोफेसर– सभी को भारी कीमत चुकानी पड़ती है। यह बात गरीबों के हित में नहीं है।

माओवादी चुनौती पर

जिस प्रकार से माओवादी आंदोलन पशुपति से तिरूपति तक फैला है, उससे यूपीए सरकार की गलत नीतियों का पता चलता है। आंध्र प्रदेश चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने नक्सलवादियों और उनके समर्थकों के साथ समझौता किया। राजनैतिक प्रयोजन के लिए वे नक्सलवादियों से मदद लेते हैं। हम महसूस करते हैं कि यह बड़ी–बड़ी समस्याएं फैलाने वाला विषय है। यह राष्ट्र के खिलाफ है। जहां तक सरकार का प्रश्न है, आतंकवाद से लड़ने के लिए हम सरकार को अपना पूरा समर्थन देते हैं। हम हर प्रकार के आतंकवादी तत्वों से मिल कर लड़ने को तैयार हैं।

ऐसा कुछ भाव मिलता है कि आपके पूर्व सहयोगी दल तृणमूल कांग्रेस नंदीग्राम जैसे कुछ क्षेत्रों में माओवादियों के साथ मिले हुए हैं?

हमारा तृणमूल से कोई सम्बंध नहीं है। मैं नहीं जानता कि वह दल किस प्रकार की नीति पर चलता है। परन्तु हम किसी भी राष्ट्रीय हित के साथ समझौता नहीं करते हैं, चाहे हम सत्ता में हों या न हों।

असम में राजनैतिक पार्टियां देश में विदेशियों को बुला रही हैं और वे उन्हें मताधिकार दे रहीं हैं– हम इस प्रकार की राजनीति का विरोध करते हैं।

जब भाजपा विकास पर विशेष ध्यान देती है तो वह क्यों अयोध्या मुद्दे को हटा नहीं देती?

जहां तक राम मंदिर मुद्दे का प्रश्न है, मैं पहले ही इन्दौर में अपने अध्यक्षीय भाषण में अपनी नीति की घोषणा कर चुका हूं। हम समझते हैं कि यह हमारी अस्मिता का प्रश्न है। हम केवल उस स्थान को जानते हैं जहां राम का जन्म हुआ था। अतः यह करोड़ों लोगों की आस्था का प्रश्न है। हम समझते हैं कि वहां राममंदिर का निर्माण होना चाहिए। हम इस मुद्दे से पीछे नहीं हटेंगे। ■

रामसेतु तोड़े बिना ढूंढ़ो कोई मार्ग : सुप्रीम कोर्ट

राम सेतु तोड़े बगैर सेतु समुद्रम परियोजना का वैकल्पिक मार्ग तलाशने की संभावनाएं जांचने के लिए सुप्रीमकोर्ट ने सरकार को एक वर्ष का समय दे दिया है। मुख्य न्यायाधीश केजी बालाकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केन्द्र सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एच पी रावल की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई अगले वर्ष फरवरी तक के लिए टाल दी। रावल का कहना था कि वैकल्पिक मार्ग की संभावनायें जांचने

के लिए सरकार ने आर के पचौरी की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है, जिसने इस वर्ष जनवरी से काम भी शुरू कर दिया है। लेकिन विशेषज्ञ समिति का कहना है कि परियोजना के पर्यावरण प्रभाव आंकलन के लिए पूरे वर्ष यानी 365 दिनों के मौसम का अध्ययन करना जरूरी है। इस समय में कटौती नहीं की जा सकती है क्योंकि वैज्ञानिक नतीजे पाने के लिए पूरे साल का अध्ययन करना ही पड़ेगा तभी पता चल पायेगा कि परियोजना का क्या प्रभाव होगा। रावल ने कहा कि विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट के मुताबिक जांच का समय कम नहीं हो सकता क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च के मौसम के जो अध्ययन नतीजे होंगे वे अगले मौसम में नहीं होंगे। दूसरी ओर से पेश जनता पार्टी अध्यक्ष सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वे सरकार की बात का समर्थन करते हैं, लेकिन कोर्ट वर्तमान सेतु समुद्रम की वर्तमान परियोजना को रद कर दे क्योंकि यह तय हो गया है कि परियोजना बिना पर्यावरण प्रभाव आंकलन के लागू की गयी थी। कोर्ट उनकी दलीलों से सहमत नहीं हुआ। पीठ ने कहा कि जब सरकार वैकल्पिक मार्ग पर विचार कर रही है तो फिर वर्तमान परियोजना पर बहस कैसी। स्वामी ने यह भी कहा कि सरकार को इस बीच राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने पर विचार करने का भी निर्देश दिया जाये। उन्होंने कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसा आदेश दिया था और सुप्रीमकोर्ट ने भी सरकार से हाईकोर्ट के आदेश पर अमल के लिए कहा था, लेकिन सरकार ने आज तक इस बारे में कोई जवाब दाखिल नहीं किया है। हालांकि कोर्ट ने इस बारे में कोई भी आदेश जारी करने से मना कर दिया। ■

महंगाई का सवाल

13 विपक्षी दलों की वित्त विधेयक पर कटौती प्रस्ताव लाने की तैयारी केंद्र सरकार के लिए खतरे की घंटी से कम नहीं। चूंकि भाजपा भी कटौती प्रस्ताव लाने के पक्ष में है और लालू यादव तथा मुलायम सिंह महंगाई के सवाल पर विपक्ष के साथ हैं इसलिए सरकार के सामने संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। यदि बसपा भी कटौती प्रस्ताव के पक्ष में आ खड़ी होती है तो संप्रग सरकार गिरने की कगार पर भी आ सकती है। निःसंदेह केंद्र सरकार विपक्षी दलों के इस कथन पर भरोसा नहीं कर सकती कि उनका इरादा सरकार गिराने का नहीं है। वैसे भी विपक्षी दलों को इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं कि कटौती प्रस्ताव का सामना करते समय सत्तापक्ष अपने बहुमत से लैस रहे।

यह सही है कि सपा–राजद के कटौती प्रस्ताव के पक्ष में खड़े होने और बसपा के साथ की गारंटी न मिलने के बाद भी सरकार 272 के जादुई आंकड़े को छूने में समर्थ है, लेकिन किसी भी सरकार के लिए यह सुकून वाली स्थिति नहीं कि वह किसी तरह बहुमत में है। अपने या सहयोगी दलों के दो–चार सांसदों की अनुपस्थिति सरकार पर भारी पड़ सकती है। इसकी भी अनदेखी नहीं की जा सकती कि संप्रग के कुछ घटक दल सरकार से नाखुश हैं। कटौती प्रस्ताव का कुछ भी हो, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि महंगाई के सवाल पर खुद की चौतरफा घेरेबंदी के लिए खुद सरकार ही जिम्मेदार है।

ऐसा लगता है कि उसे न तो महंगाई विरोधी भाजपा की रैली से कोई फर्क पड़ा है और न ही 13 विपक्षी दलों की आगामी राष्ट्रव्यापी हड़ताल से। दुर्भाग्य से ऐसा तब है जब सरकार स्वयं मान रही है कि आवश्यक वस्तुओं के दाम चढ़े हैं और इससे आम जनता की मुसीबतें बढ़ी हैं। इसका कोई मतलब नहीं कि यह तो माना जाए कि महंगाई बढ़ रही है, लेकिन उसे थामने के लिए कुछ न किया जाए। यह विचित्र है कि केंद्र सरकार यह बताने की भी स्थिति में नहीं कि आवश्यक वस्तुओं के दाम इतने अधिक क्यों बढ़े हैंघ् कभी अंतरराष्ट्रीय हालात का रोना रोया जाता है, कभी कम पैदावार को, कभी जमाखोरी को और कभी राज्यों के असहयोग को।

महंगाई के इन कारणों पर यकीन करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि तथ्य ये हैं कि अन्य देशों में महंगाई इतनी बेकाबू नहीं हुई और अन्न भंडारों में सड़ते गेहूं तथा बंदरगाहों में जमा कच्ची चीनी ने सरकारी दावों की कलई खोल दी। इसी तरह कोई भी यह मानने को तैयार नहीं कि कांग्रेस शासित राज्यों में महंगाई काबू में है। यदि केंद्र सरकार महंगाई के मूल कारण भी नहीं बता पा रही है तो फिर यह उम्मीद करना व्यर्थ है कि वह उनका निवारण कर सकेगी।

सच तो यह है कि ऐसी कोई कोशिश की भी नहीं गई और आगे भी ऐसे आसार नहीं नजर आते। यद्यपि महंगाई के लिए गैर कांग्रेस शासित राज्य सरकारें खुद को पाक–साफ नहीं बता सकतीं, क्योंकि एक ओर वे मूल्य वृद्धि से हलकान आम आदमी की परेशानी रेखांकित कर रही हैं और दूसरी ओर किस्म–किस्म के कर भी लगा रही हैं। बावजूद इसके केंद्र सरकार को यह अधिकार नहीं कि वह आर्थिक कुप्रबंधन के साथ–साथ संवेदनहीनता का परिचय दे। दुर्भाग्य से वह ठीक यही कर रही है। वह जिस तरह संकट से घिरती दिख रही है उससे यह भी साफ है कि उसका राजनीतिक प्रबंधन भी दुरुस्त नहीं।■

(संपादकीय जागरण)

भारतीयों के स्वास्थ्य पर एक नजर

बढ़ती आबादी और घटता बजट

çHkkr >k

HkkRत में सरकारों को चाहे वह केन्द्र की हो या राज्यों की, उन्हें आम आदमी की बुनियादी बातों पर सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। प्राचीन काल से ही भारत में शासन व्यवस्था का आधार कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना रहा है। इसका सबसे बेहतर उदाहरण गरीबों एवं निराश्रितों को सुसंगठित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना रहा है। चीनी यात्री फाह्यान, जिसने भारत की यात्रा चन्द्रगुप्त मौर्य के कार्यकाल में की थी, उसने पाटिलपुत्र में चलाए जा रहे धर्मार्थ औषधालय का विस्तार में वर्णन किया है। फाह्यान के अनुसार, भारत में भद्रजनों और यहां के निवासियों ने शहरों में अस्पतालों का निर्माण कर रखा था और वहां इलाज के लिए सभी देशों के लोग आते थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग, जो हर्षवर्द्धन का समकालीन था, उसने उस समय के अस्पतालों का विस्तार से वर्णन किया है। उसके अनुसार पूरे भारत में शहरों एवं गांवों में वहां से गुजरने वाले उच्चपथों पर शासन द्वारा संचालित अस्पताल (पुण्यशाला) थे।

आज आजादी के 62 सालों बाद हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहां खड़े हैं, पर विचार करते हैं तो लगता है सरकारें स्वयं बीमार हो चुकी हैं और उनके शासन की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। स्वास्थ्य मानव का प्राथमिक अधिकार है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में यह बात स्पष्टता एवं सबलता के साथ कही गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पोषण राज्य सरकारों के जिम्मे है जबकि केन्द्र सरकार को इसमें महत्वूपर्ण भूमिका निभानी है।

वर्तमान शासन व्यवस्था में (संविधान के अनुसार) स्वास्थ्य समवर्ती सूची में है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाले सरकारी व्यय का तीन चौथाई हिस्सा राज्य एवं स्थानीय सरकार द्वारा वहन किया जाता है। देश में स्वास्थ्य का राष्ट्रीय मानक निर्धारण करना तथा उसका नियमन एवं मॉनिटरिंग करना केन्द्र सरकार का उत्तरदायित्व है।

हमारे देश में जनसंख्या वृद्धि दर 2 प्रतिशत के आसपास है तथा एक अनुमान के अनुसार 2030 तक भारत चीन को पीछे छोड़ते हुए विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन जायेगा। सन् 2025 तक देश में 189 मिलियन लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के हो जायेंगे, जिसके परिणामस्वरूप उच्चतर स्वास्थ्य सेवा खर्च की आवश्यकता होगी। विश्व के 18 प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं और विश्व के कुल रुग्णता का 21 प्रतिशत भारत में हैं। जबकि स्वास्थ्य पर सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद का एक प्रतिशत से भी कम है। हम अपनी बढ़ती जनसंख्या को बुनियादी एवं गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं तभी उपलब्ध करा सकते हैं जब स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र पर सरकारी व्यय सकल घरेलू उत्पाद का 2.3 प्रतिशत हो।

अब एक नजर हम सरकारी रिपोर्ट और आर्थिक समीक्षा (2009–10) पर डालें तो देश के ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु 6,800 से अधिक अस्पतालों की आवश्यकता है। सन् 2001 के जनसंख्या मापदंडों के आधार पर अभी भी 20,486 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 4,447 उपेन्द्रों और 2,337 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की कमी है। यह बात

...शेष पृष्ठ 26 पर

आज आजादी के 62 सालों बाद हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में कहां खड़े हैं, पर विचार करते हैं तो लगता है सरकारें स्वयं बीमार हो चुकी हैं और उनके शासन की प्राथमिकताएं बदल चुकी हैं। स्वास्थ्य मानव का प्राथमिक अधिकार है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 21 में यह बात स्पष्टता एवं सबलता के साथ कही गई है। इस अनुच्छेद के अनुसार लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा एवं पोषण राज्य सरकारों के जिम्मे है जबकि केन्द्र सरकार को इसमें महत्वूपर्ण भूमिका निभानी है।

माओवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़नी होगी : भाजपा

गत 6 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में माओवादियों ने बर्बर हमले कर सीआरपीएफ के 76 जवानों को घेर कर मार डाला। संसद में इस हमले पर हुयी चर्चा में भाजपा सांसदों ने आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर केन्द्र सरकार की नीतियों पर जमकर प्रहार किया। राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष श्री अरूण जेटली एवं लोकसभा में श्री यशवंत सिन्हा ने चर्चा की शुरुआत करते हुए माओवाद को खत्म करने को लेकर सरकार में इच्छाशक्ति नहीं होने का आरोप लगाया। हम यहां उनके भाषणों का संपादित अंश प्रकाशित कर रहे हैं :—

अरूण जेटली

हम सभी अपने सुरक्षा बलों पर इस निर्दयतापूर्ण हमले की भर्त्सना करते हैं जिसमें हमारे 75 सुरक्षाकर्मी मारे गये। पिछले कई वर्षों से छत्तीसगढ़ माओवादी समस्या से प्रभावित रहा है। यह समस्या अत्यंत गंभीर और व्यापक है क्योंकि माओवादी आंदोलन का सैनिकीकरण हो गया है। इस मुद्दे पर सरकार के साथ विचार–विमर्ष हुआ है जिसका कहना है कि केवल सामाजिक और आर्थिक विकास से इस समस्या का समाधान हो जायेगा। सरकार का दृष्टिकोण यथार्थवादी नहीं है क्योंकि माओवादी देश के कम से कम 220 जिलो में उपस्थित हैं। इसे किसी सत्याग्रह के माध्यम से नहीं सुलझाया जा सकता है।

वास्तव में, हमने इस समस्या की गंभीरता को नहीं समझा है। हमें दृढ़ मस्तिष्क और मजबूत दिल से लड़ाई लड़नी होगी ताकि माओवाद के अभिशाप का खात्मा किया जा सके। इसके लिए विपक्ष, सरकार और समस्त देश संगठित है क्योंकि हमें माओवाद के विरूद्ध लड़ाई को शिथिल नहीं पड़ने देना है। राजनीतिक दलों ने यह कहकर कि वे सभी हिंसा के विरूद्ध लड़ाई में संगठित हैं, अपनी परिपक्वता और बेहतर नेतृत्व का प्रदर्शन किया है। सरकार माओवादियों की उपस्थिति के बारे में भ्रामक वक्तव्य दे रही है। मैं समझता हूं कि माओवादियों के सैनिकीकृत आंदोलन का सामना कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में करना होगा।

इस प्रकार के अभियान में, सुरक्षा बलों को निगरानी रखने और सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ाने के प्रयोजन से वायु सेना से सहायता के जरूरत पड़ सकती है। ऐसे वक्तव्य दिए जाने के तत्काल बाद हमारे सामने दूसरे वक्तव्य आ जाते हैं जिनमें यह कहा जाता है कि यह सहायता नहीं दी जाएगी। यदि इस प्रकार का दृष्टिकोण है तो मैं माननीय गृह मंत्री को यह सलाह और सुझाव दूंगा कि इस देश की आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी हो हार नहीं सकता और इसलिए यह लड़ाई लड़ी जानी चाहिए और हम विपक्ष के लोग माओवाद से लोहा लेने के लिए मामले में सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तैयार हैं बशर्ते सरकार ऐसा करने की इच्छा रखती हो।

यह केवल आर्थिक विषमता और निर्धनता का ही मामला नहीं है। यदि प्रत्येक नागरिक जो अपने आपको बिल्कुल निर्धन मानता है और बंदूक उठा लेता है तो फिर हमें इस देश को एक रखने तथा अपने संसदीय लोकतंत्र को बचाने के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। यह एक राजनीतिक आंदोलन है जिसका नेतृत्व वैचारिक दृष्टि से कट्टर व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है जो हिंसा का प्रयोग करके भारत के संसदीय लोकतंत्र को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। यह वस्तुतः माओवादी आंदोलन है। उन लोगों ने अपना एक अलग क्षेत्र बना लिया है जिनमें उनका बाहुल्य है अैर उन क्षेत्रों में हमारी सशस्त्र सेना तथा सुरक्षा बल प्रवेश करने में समर्थ नहीं हैं। इन क्षेत्रों में 220 जिलों विशेषकर 90 जिलों पर उनका मजबूत नियंत्रण है। जहां प्रत्येक कर्मचारी जिसे वेतन मिलता है प्रत्येक दुकानदार, प्रत्येक किसान और प्रत्येक ठेकेदार को कर देना पड़ता है उन क्षेत्रों में अफीम की खेती की जाती है जो कि उनके राजस्व का स्रोत है

और प्रत्येक वर्ष उससे उन्हें 1500 करोड़ रूपए की आमदनी होती है। इस धन के बल पर उन लोगों ने कैडरों की भर्ती करनी शुरू कर दी है, जो कि अब वैचारिक कारणों से भर्ती नहीं हो रहे हैं क्योंकि उन्हें युवा बेरोजगार जो कि अवसरों के अभाव में निराश हो जाते हैं, मिलने लगे हैं।

निश्चय ही प्रत्येक व्यक्ति आजीविका पाने का हक है। सरकार की कुछ योजनाओं पर किसी को भारी आपत्ति हो सकती है। लेकिन कुछ योजनाएं ऐसी हैं जिन पर व्यापक राष्ट्रीय सहमति है और वे योजनाएं विभिन्न सरकारों के समय में जारी रही हैं। इस बात की जांच की जा सकती है कि इन योजनाओं के अधीन दी जाने वाली राशि भी इन लोगों के नियंत्रित क्षेत्रों में पहुंच जाती है और गरीबों के लिए दिया गया सरकार का धन जबरन ऐंठ लिया जाता है तथा उसका उपयोग माओवादी आंदोलन चलाने के लिए किया जाता है।

हमें यह याद रखना चाहिए कि किसी राजनीतिक समस्या या सामाजिक समस्या के साथ हिंसा की आशंका भी जुड़ी रहती है। और उससे कानून और व्यवस्था का संघटक बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता। यह भी याद रखना महत्वपूर्ण है कि सामाजिक और आर्थिक गतिविधि तथा सुरक्षा कार्यवाही के अलावा हमें उन लोगों के साथ वैचारिक लड़ाई लड़ने की भी जरूरत है। हमें इसके बारे में गरीब लोगों के पास जाकर बताने की जरूरत है।

हमें केन्द्र और राज्यों के बीच भारी समन्वय रखने की जरूरत है। हमें एक दूसरे पर केवल दोषारोपण नहीं करना चाहिए राज्यों में विभिन्न दलों की सरकार हो सकती है तथा केन्द्र में अलग दलों का शासन हो सकता है। इस मुद्दे पर लोकतांत्रिक दलों के बीच वैचारिक मतभेद सामने नहीं आने चाहिए। इसलिए हमें इस संपूर्ण कार्यवाही के मामले में समन्वय बरतने की जरूरत है।

प्रकाश जावडेकर

अगर नक्सलवादियों के खिलाफ हमें लड़ाई जीतनी है तो किसी भी राजनीतिक लाभ के लिए नक्सलियों का साथ नहीं लेना चाहिए। नक्सलवादियों की मदद लेकर चुनाव जीतने का प्रयास हुआ और उसके कारण नक्सलवादियों को कई रियायतें दी गईं। आंध्र प्रदेश में चुनाव के तुरंत बाद सीजफायर की घोषणा हुई। आज जो दंतेवाड़ा में हो रहा है उसका मूल आंध्र में है, क्योंकि गए साल के उस सीजफायर में सारे नक्सली वहां एकत्र हो गए और उन्होंने दंतेवाड़ा में डेरा जमाया।

किसी भी सूरत में नक्सलियों का सहारा लेकर, उनकी सहायता लेकर चुनाव की राजनीति नहीं होनी चाहिए। नक्सलवाद को सहयोग देने वालों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। नक्सलवादियों को असला और गोला–बारूद देने वाले कितने लोगों को, कितने गैंग्स को समाप्त किया गया है? दो महीने पहले, लैटिन अमरीकन देशों से नक्सलवादी, माओवादियों के सहयोगी दंतेवाड़ा के जंगल में आए थे। उनको कैसे आने दिया गया और क्यों नहीं पकड़ा गया, यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। आज कोई खुफिया तंत्र नहीं है। नक्सलियों को पता चल जाता है कि जवान कहां से जाने वाले हैं, लेकिन जवानों को पता नहीं चलता कि नक्सलवादी कहां जमा हुए हैं। जो जवान वहां पर जंगल में लड़ने के लिए जो रहे हैं, उनके लिए कोई भी सुविधा नहीं है। आस–पास ऐसा वातावरण है कि उनको मनोबल गिर रहा है। इसलिए यह भी बदलना चाहिए।

अगर हमें लोगों के अनुकूल प्रशासन चलाना है तो विकास भी जल्द होना चाहिए, न्याय और सेवाएं भी जल्द होनी चाहिए लेकिन एक राजनैतिक प्रतिज्ञा करनी होगी कि हम नक्सलवादियों को लड़ाई में खत्म करेंगे।

लोक सभा

यशवंत सिन्हा

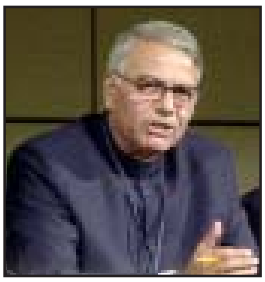

हमारे आंतरिक सुरक्षा के इतिहास में मंगलवार, 6 अप्रैल, 2010 का दिन काले दिन के रूप में लिखा जाएगा। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के जंगलों में माओवादियों द्वारा घात लगाकर 73 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी। स्वतंत्र भारत के इतिहास में इससे पहले किसी विद्रोही समूह द्वारा एक ही हमले में इतने अधिक सुरक्षाकर्मियों को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ी। यह भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान, हमारे सभी विकास प्रयासों की असफलता और इस सरकार की कार्यशैली को दर्शाता है। हम उनकी मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हैं तथा उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। घटना के तुरन्तु बाद हमारी पार्टी ने एक वक्तव्य जारी किया था जिसमें हमने यह घोषणा की थी कि माओवादियों के साथ लड़ाई में हम सरकार के साथ एकजुट खड़े हैं। अब प्रश्न यह है कि जब विपक्ष इस लड़ाई में सरकार के साथ है तो क्या कांग्रेस पार्टी सरकार के साथ है? क्या

सं॰प्र॰ग॰ सरकार के साथ है? जब इस लड़ाई में हम सबको एक साथ होने की आवश्यकता है, सत्ता गठबन्धन पूरी तरह से विभाजित दिख रहा है। जब तक सरकार में उद्देश्य की एकता और कड़ी कार्यवाही करने का दृढ़निश्चय नहीं होगा तब तक हम यह युद्ध नहीं जीत सकते हैं। दंतेवाड़ा में जो घटना घटी, वह कितनी गंभीर थी, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि तीन घंटे तक हमारे जवान मुकाबला करते रहे, मारे जाते रहे। उन्होंने सहायता के लिए संदेश भेजे। किंतु हम उनको सहायता नहीं भेज पाये। 10 दिनों में गृह मंत्रालय से इतनी गंभीर घटना पर एक स्टेटमेंट भी तैयार नहीं हो सका। पिछले 6 वर्षों में सुरक्षाबलों के जवानों सहित 4,246 इन माओवादी हमलों में मारे गए हैं। इन मारे गए लोगों में से 50 प्रतिशत से अधिक लोग अकेले छत्तीसगढ़ और झारखंड में मारे गए हैं जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच विभिन्न युद्धों में मारे गए लोगों से अधिक है। अगर माओवाद से लड़ने की नीति में स्पष्टता नहीं होगी, अगर उसमें दृढ़ निश्चय नहीं होगा तो हम एक लड़ाई में मात खाते रहेंगे। आपरेशन ग्रीन हंट बिना पूरी तैयारी के शुरू किया गया। इसमें जिस तरह से राज्यों को विश्वास में लेना चाहिए था, वह काम नहीं किया गया। कार्यवाही की योजना अन्य स्तरों पर की जाती है। इसकी योजना गृह मंत्री या मुख्यमंत्री के स्तर पर नहीं बल्कि प्रभारी पुलिस के स्तर पर की जाती है। यह ऑपरेशन ग्रीन हंट क्या है? इसकी योजना किस प्रकार बनाई गई है। इसके लिए राज्यों को विश्वास में लिया गया है या नहीं और राज्य सरकारों के साथ इस प्रकार का समन्वय स्थापित किया गया। दंतेवाड़ा की घटना में हमने ठीक उसी प्रकार बिना तैयारी के अपने जवानों को झोंका जैसे 1962 में चीन के साथ युद्ध में जवानों को झोंका था। कुछ सदस्य केन्द्र–राज्य सहयोग की बात कर रहे थे कि यह राज्यों का मुद्दा है। यह सिर्फ राज्यों का मुद्दा नहीं है।

बार–बार बयान आता है कि जिम्मेदारी इसकी है या उसकी है किन्तु मेरा मानना है कि जिम्मेदारी इस संसद की है। जब तक हम सब इसके लिए एकजुट नहीं होंगे, तब तक यह लड़ाई नहीं रुकेगी। यदि राज्यों और जनता के साथ समन्वय नहीं होगा तो ऑपरेशन ग्रीन हंट या कोई भी ऑपरेशन सफल नहीं हो सकता। दांतेवाड़ा की घटना के बाद मीडिया में लेख छपे और टेलीविजन चैनलों पर दिखाया गया कि हमारे सुरक्षा बल किस हालत में अपने कैम्प्स में रह रहे हैं।

केन्द्रीय बलों के जवानों को शिविरों में मूलभूत सुविधाएं नहीं हैं। क्या यह हमारा राष्ट्रीय कर्त्तव्य नहीं है कि जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि अपनी जान पर खेलकर देश की रक्षा करें उनकी थोड़ी बहुत हम चिन्ता करें? क्या भारत सरकार का कोई व्यक्ति दंतेवाड़ा में मारे गए जवानों के परिवारों को सांत्वना देने के लिए गया? क्या उनको मुआवजे की राशि मिल गई? क्या उनके आश्रितों को नौकरी मिल गई? हमारे देश में छद्म उदारवादी हैं। वे माओवादियों का समर्थन करते हैं। इन 76 जवानों के मानवाधिकार के बारे में एक भी छद्म उदारवादी नहीं बोला। इन छद्म उदारवादियों ने इन जवानों के परिवारों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखायी। ऐसे छद्म उदारवादी के मशविरे की देश को जरूरत नहीं है।

आजकल राज्य पुलिस और केन्द्रीय बलों में जो ड्रिल करने की परम्परा थी वह समाप्त हो गई है। आजकल पुलिस में चांदमारी नहीं होती है। अगर पुलिस ट्रेनिंग का यह स्तर है तो क्या होगा? इसलिए धीरे–धीरे राज्य सरकारें पूरी तरह से केन्द्रीय बलों पर निर्भर हो गई हैं। आज राज्य पुलिस अपनी सुरक्षा स्वयं करने में अक्षम हैं। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि पुलिस आधुनिकीकरण के लिए जिस भी चीज की आवश्यकता है, उसकी पूरी–पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। पुलिस के पास समुचित हथियार, उपकरण और वाहन नहीं हो।

देश में माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में एक बड़ा हिस्सा उनके नियंत्रण में है। वहां पर उनका शासन चलता है। एरिया डॉमिनेंस एप्रोच में हम क्या कर रहे हैं? हम कितना अंदर जाने को तैयार हैं? यह काम राज्य बलों से नहीं होगा। इसके लिए केन्द्रीय बल को ही लगाना पड़ेगा। उनको वहां जाकर अच्छे कैंप्स स्थापित करने पड़ेंगे। वहां पर जाकर पूरे क्षेत्र में अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन इस काम में लोगों को अलग–थलग नहीं होने देना होगा। जनता का सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है तथा जनता के सहयोग में इंटेलिजेंस भी सम्मिलित है। जब कोई घटना घटती है तो कहा जाता है कि खुफिया सूचना उपलब्ध कराई गई और यह उपलब्ध थी किन्तु क्या वह वास्तविक खुफिया सूचना थी। क्या यह सूचना ऐसी थी जिस पर कार्यवाही की जा सकती थी। दंतेवाड़ा की घटना के बाद सुरक्षा की भावना इस देश में समाप्त हो गई है और वह उस समय तक नहीं लौटेगी, जब तक हम इस खतरे पर काबू नहीं पा लेते। देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़े पेशेवर मामलों की समीक्षा करने के लिए गृह मंत्री के साथ केन्द्रीय अर्द्ध–सैनिक बलों के काडर अधिकारियों की संस्थागत आवधिक बैठकों की प्रणाली को औपचारिक स्वरूप दिए जाने की आवश्यकता है। केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के ऐसे विभिन्न प्रस्तावों की जांच

के लिए गृह मंत्रालय में केन्द्रीय अर्द्धसैनिक बलों के अनुभवी अधिकारियों को तैनात किया जाए जिनका इन बलों के कार्यकरण पर प्रभाव पड़ता हो। पारदर्शी कमान और नियंत्रण प्रणाली बनाई जाए ताकि प्रत्येक पांच यूनिटों के ऊपर डीआईजी स्तर का एक अधिकारी हो जो इन यूनिटों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण और निगरानी करे और प्रत्येक 15 यूनिटों के ऊपर उनके कार्यकरण के पर्यवेक्षण के लिए एक आईजी स्तर का अधिकारी नियुक्त किया जाए ताकि नक्सल रोधी कार्यवाही की योजना बनाने में और उन्हें लागू करने में संचालनात्मक और युक्ति चूक न हों। समय पर पदोन्नति सुनिश्चित करने और फील्ड में रिक्तियों को भरने के लिए सिपाहियों, एसओ और अधिकारियों के लिए कैरियर प्लानिंग और मैनेजमेंट सेल की स्थापना की जाए। राज्य और केन्द्रीय पुलिस अधिकारियों के बीच स्वस्थ, प्रभावी और सक्षम संयुक्त कार्यप्रणाली विकसित की जाए ताकि समान वरिष्ठता वाले अधिकारी ठोस ढंग से योजना बना सकें और मिलकर कार्य कर सकें।

यदि नक्सलवाद प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्य नहीं किए गए तो यह सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। ये क्षेत्र देश में सबसे गरीब और पिछड़े क्षेत्र हैं। वहां बिजली, पानी, अस्पताल की व्यवस्था नहीं है। उन तक पैसा नहीं पहुंच रहा है। सरकार को 9–10 राज्यों के 32–33 नक्सलवाद प्रभावित जिलों के लिए विशेष विकास योजना बनानी चाहिए। इन जिलों में कुशल और ईमानदार अधिकारियों की तैनाती की जाए तथा उनका वहां निश्चित कार्यकाल निर्धारित किया जाए। हम इस लड़ाई में तभी विजय प्राप्त कर सकते हैं जब हम हर मामलें में माओवादियों से आगे रहें। ■

संसद में सड़े गेहूं की गूंज

करीब की खाली थाली और सरकारी गोदामों में खुले आसमान के नीचे सड़े रहे लाखों टन गेंहू की गूंज संसद में जोरदार ढंग से हुई। इसके पीछे भारी घोटाले की आशंका व आपराधिक लापरवाही के तीखे आरोप लगाते हुए विपक्ष ने संसद की सयुंक्त समिति से जांच करने की भी मांग की। साथ ही कहा कि राशन की दुकानों में अच्छे गेहूं के साथ इस सड़े गेहूं को मिलाकर बेचने पर रोक लगाई जाए। इस आवाज को सरकार ने नोट तो किया, लेकिन जवाब के लिए अभी इंतजार करना होगा। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राजनाथ सिंह ने पिछले सप्ताह हरियाणा के एफसीआई गोदामों का दौरा कर सड़े गेहूं के

जो नमूने लिए थे, उन्हें लेकर वे संसद भी पहुंचे। सदन शुरू होते ही उन्होंने यह मामला उठाया, लेकिन बोलने का अवसर शून्यकाल में मिला।

श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि एक तरफ तो गरीब की थाली में अन्न नहीं है, दूसरी तरफ सरकारी गोदामों में दो साल से खुले में लाखों टन गेहूं सड़ रहा है। यह ऐसा गेहूं है जिसे जानवर भी नहीं खा सकते हैं, लेकिन इसे अच्छे गेहूं के साथ मिलाकर सरकारी राशन की दुकानों पर बेचा जा रहा है। उन्होंने सरकार से मांग की कि संसद की संयुक्त संसदीय समिति बनाकर जांच की जाए कि देश में सालाना इस तरह कितना खाद्यान्न नष्ट होता है और एफसीआई के गोदामों में अब तक इस तरह का कितना गेहूं सड़ चुका है।

भाजपा के डा. मुरली मनोहर जोशी ने भी इसका समर्थन करते हुए जेपीसी की मांग पर जोर दिया। सपा नेता श्री मुलायम सिंह यादव व जनता दल (यू) के श्री शरद यादव ने भी राजनाथ सिंह की मांग का समर्थन करते हुए कहा कि इसके कारण किसानों की नई फसल की खरीद नहीं हो पा रही है। किसान समर्थन मूल्य से कम पर बिचौलियों को गेहूं बेचने पर मजबूर हैं। कांग्रेस के जगदंबिका पाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब तक खरीद के लिए केंद्र तक नहीं खोले गए हैं, जिसके कारण लक्ष्य से बेहद कम की खरीद की जा सकी है। बाद में संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने सदन को आश्वासन दिया कि वह उनकी भावनाओं से संबंधित मंत्री को अवगत कराएंगे।

राज्यसभा में इस मामले को भाजपा सांसद श्री प्रभात झा ने उठाया। श्री झा ने एफसीआई की रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले छह–सात वर्षों में दस लाख टन से ज्यादा खाद्यान्न उसके गोदामों में सड़ गया। इस अनाज से एक साल तक एक करोड़ लोगों को भरपेट भोजन मुहैया कराया जा सकता था। इस समय जबकि नई खरीद शुरू हो गई है तो गोदामों में रखने को जगह तक नहीं है। ■

नक्सली चाहते हैं लोग २०वीं सदी में जिएं : डा. रमन सिंह

नक्सलवाद पर हमने जो पहल की है, उसे लोग अच्छा कहें, बुरा कहें, पर अब सबको समझ में आ रहा है कि नक्सलवादी क्या चाहते हैं, उनकी वास्तविकता क्या है और हम किस तरह काम कर रहे हैं। नक्सली आज भी लोगों को 20वीं सदी का जीवन देना चाहते हैं, इसलिए विकास के कामों में बाधा डाल रहे हैं। जबकि हम चौतरफा विकास के लिए निरंतर प्रयासरत हैं और इसके परिणाम दिख रहे हैं। नक्सलियों से सहानुभूति रखने वाले, उनके पक्षधर मानवाधिकारों की बात करते हैं। जबकि नक्सली लगातार मानवता के खिलाफ काम कर रहे हैं। ऐसा मानना है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह का। समाचार पत्र देशबन्धु ने उनसे हाल में हुए दंतेवाडा के नृशंस हमले के बाद नक्सल समस्या, उसके समाधान, केंद्र व राज्य के बीच इस पर तालमेल व मानवाधिकार संगठनों की भूमिका पर विस्तृत चर्चा की। पेश हैं इस बातचीत के प्रमुख अंश :

नक्सलियों ने अब तक की सबसे बड़ी घटना ७६ लोगों की मौत को अंजाम दिया, चूक कहां हुई?

इसको तो शहादत बोलते हैं, मौत नहीं। बहुत बुरी घटना हुई है। फिर भी हम जिस मॉडल पर काम कर रहे हैं, उसी से निराकरण होगा। प्रधानमंत्री, गृहमंत्री भी इससे सहमत हैं। मजबूती के साथ खड़े होकर काम करने की शुरुआत हमने की है। नक्सल समस्या से निपटने के लिए जो पहल हम लोगों ने की है, आज इस घटना के बाद भी केंद्र में यह बात मानी जा रही है कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सल समस्या के खिलाफ जिस मॉडल पर काम कर रही है, वही सही है। पिछले छह वर्षों में जिस कार्ययोजना पर हम काम कर रहे हैं, अब उस पर देश भर में सहमति बन रही है। पहले राष्ट्रीय मीडिया में इसे लेकर असमंजस दिख रहा था, पर अब उसे भी समझ में आ रहा है कि वास्तविकता क्या है।

क्या सलवा जुडूम खत्म हो गया है?

केवल प्रारूप बदला है। सलवा जुडूम में धरना–प्रदर्शन होता था, 10.10 हजार लोगों की भीड़ होती थी। आदिवासी जुलूस के माध्यम से नक्सलियों का विरोध करते थे। यह सब आदिवासी स्वतःस्फूर्त करते थे। आज भी आदिवासी शत प्रतिशत हमारा साथ दे रहे हैं। तीन साल तक हमने उन्हें शिविर में रखा। अब वे शिविर से अपने गांव भी जाते हैं। तेंदुपत्ता तोड़ते हैं महुआ पीते हैं। तो कह सकते हैं कि स्वरूप बदला है। लोकसभा, विधानसभा, पंचायत, नगर निगम चुनाव में हमारी जीत यह बताती है कि वे हमारे साथ हैं। जबकि इन क्षेत्रों में वामपंथियों की, नक्सलियों से सहानुभूति रखने वालों की हार हुई है।

नक्सलियों के खिलाफ हवाई हमले की बात हो रही है, क्या आप इसके पक्षधर हैं?

मैं पहले दिन से हवाई सहायता की बात कर रहा हूं। हवाई सहायता इस संदर्भ में कि कोई घायल हो गया है, तो उठा कर अस्पताल तक पहुंचाना है। आपात स्थिति में सहायता, अचानक सुरक्षा बल पहुंचाने की आवश्यकता या रणनीतिक मदद पहुंचाने के लिए हवाई सहायता चाहिए। हमला करने के लिए नहीं। अगर हवाई हमला होता है तो निरीह आदिवासियों की जान को भी खतरा

रहेगा। बस्तर कोई दुश्मन देश तो नहीं, जहां हवाई हमले की बात सोची जाए। हांलाकि अब भी केंद्र से हवाई सहायता आवश्यकतानुसार मिलती है, पर जरूरत और ज्यादा है।

यह बात होती है कि नक्सलियों के साथ राजनेताओं और व्यापारियों की सांठ-गांठ है। तभी कई उद्योग वहां फल-फूल रहा है, राजनेता भी आराम से नक्सल प्रभावित इलाकों में जा पाते हैं। अभी आप भी ग्राम सुराज अभियान के तहत बस्तर के गांवों मेंचौपाल लगाने पहुंचे। आप पर भी इसी तरह का आरोप लगाया जाता है।

नक्सलियों की मेहरबानी से सरकार नहीं चलती। बीते कई बरसों में कई कार्यकर्ता और कई राजनेता नक्सलियों के द्वारा मारे गए। भाजपा के वरिष्ठ नेता बलिराम कश्यप के बेटे और कांग्रेस के आदिवासी नेता महेन्द्र कर्मा के भतीजे की भी जान नक्सलियों ने ले ली। तो ऐसा नहीं है कि वे राजनेताओं के साथ नरमी दिखा रहे हों। हम तो उस क्षेत्र में जाने से पहले सोच कर जाते हैं कि कोई भी घटना हो सकती है। लेकिन नहीं जाने से काम नहीं चलेगा। लोकतंत्र में जनता के बीच पहुंचना हम राजनेताओं के लिए आवश्यक होता है। सरकार भी तभी चलती है।

मानवाधिकार संगठनों के लोगों से आपकी नाराजगी है कि वे नक्सलियों के पक्षधर हैं। यह आरोप लगता रहा है कि जब नक्सली मरते हैं तो श्रे आते हैं, लेकिन अगर कोई जवान शहीद होता है तो मानवाधिकार की रक्षा करने वाले लोग चुप्पी साध लेते हैं। आप क्या सोचते हैं, ऐसा क्यों है? क्या सरकार अब तक इन संगठनों को विश्वास में नहीं ले पायी है?

जो देश विरोधी हैं, जो लोकतंत्र के विरोधी हैं, जो संविधान के विरोधी हैं, जो 76 जवानों की सरेआम हत्या कर देते हैं, अगर उनके खिलाफ मानवाधिकार संगठन आगे नहीं आता है, तो नाराजगी वाजिब है। किंतु यदि एक नक्सल नेता गिरफ्तार होता है, तो ये पूरे हिन्दुस्तान में आंदोलन करते हैं। दोहरी भूमिका है यह। धीरे–धीरे आम आदमी इनकी सच्चाई को समझने भी लगे हैं। दिल्ली में बैठकर जमीनी हकीकत को नहीं समझा जा सकता। कहां मानव और कहां उनका अधिकार।

दरअसल नक्सलियों को तो मैं मानव की श्रेणी में रखता ही नहीं हूं। उनके कार्यों मैं मानवता, मानवीय सोच सिरे से गायब है। तो फिर किनकी तरफदारी कर रहे हैं मानवाधिकार के लोग। उनकी बुद्धि और सोच समझ के बाहर है। किस दुनिया में रहते हैं और किसकी बात करते हैं।

पिछले तीस साल में विकास को रोकने वाले कौन हैं, नक्सली। घोर विरोधी हैं – विकास के, शिक्षा के। वे स्कूल, अस्पताल तोड़ते हैं। वे चाहते हैं कि लोग 20वीं सदी में जिएं। ताकि उनके कहे अनुसार सब कुछ चलता रहे। हमने बीआरओ (सीमा सड़क संगठन) को बस्तर क्षेत्र में सड़क बनाने का काम सौंपा, जो नक्सलियों की वजह से आज तक पूरा नहीं हो पाया। जबकि बीजापुर क्षेत्र में हमने सड़क का निर्माण करवाया, 14 जवान शहीद भी हुए।

कहा जाता है विकास नक्सल समस्या का हल है, तो इसके लिए क्या रणनीति है?

यह सही है कि विकास इस समस्या का हल है। और इसके लिए योजनाएं भी हैं। लेकिन विकास तभी होगा, जब नक्सली पीछे हटेंगे। वे सड़क बनते–बनते तोड़ देते हैं। जान–माल को क्षति पहुंचाते हैं।

लेकिन नक्सली इसके उलट बात करते हैं। वे कहते हैं कि विकास नहीं है, इसलिए हम हैं। उनकी बात में कितना वजन है?

पिछले तीस साल में विकास को रोकने वाले कौन हैं, नक्सली। घोर विरोधी हैं – विकास के, शिक्षा के। वे स्कूल, अस्पताल तोड़ते हैं। वे चाहते हैं कि लोग 20वीं सदी में जिएं। ताकि उनके कहे अनुसार सब कुछ चलता रहे। हमने बीआरओ (सीमा सड़क संगठन) को बस्तर क्षेत्र में सड़क बनाने का काम सौंपा, जो नक्सलियों की वजह से आज तक पूरा नहीं हो पाया। जबकि बीजापुर क्षेत्र में

हमने सड़क का निर्माण करवाया, 14 जवान शहीद भी हुए। तो ऐसा नहीं है कि विकास का काम नहीं हो रहा है। छत्तीसगढ़ में काफी विकास के काम हुए हैं। स्कूल, अस्पताल, सड़क, पुलिया सबका निर्माण हुआ है, हो रहा है। लेकिन सिर्फ नक्सल प्रभावित जो छह ब्लाक हैं उनमें ही विकास का काम क्यों नहीं हो पा रहा है। हमारी मंशा प्रदेश को उन्नति के पथ पर ले जाने की है, जिसमें हम सफल भी हो रहे हैं। लेकिन नक्सलियों को अवरोध पहुंचाने से बाज आना होगा, तभी चौतरफा विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।

आखिर समाधान क्या है? क्या वार्ता का कोई रास्ता है?

देखिए, दो चीजें जरूरी हैं। एक तो सुरक्षा बल को मजबूत करना ताकि उनके कब्जे वाले क्षेत्रों में नई चौकियों, थानों का निर्माण हो। दूसरा रास्ता विकास का है। तीसरा रास्ता जिसके बारे में हमने बातचीत की है, वह है– बेहतर आत्मसमर्पण नीति। ताकि नक्सली अगर लौट कर मुख्यधारा से जुड़ते हैं तो उन्हें बेहतर जीवन–यापन की सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। और चौथा– यदि उनके पोलितब्यूरो के सदस्य बातचीत करना चाहें तो हम तैयार हैं। हांलाकि उनकी अलग–अलग जोनल समितियां हैं और अलग–अलग नेता हैं। उनका तो प्रमुख नेतृत्व ही तय नहीं है, तो बात किससे हो। फिर भी बातचीत का विकल्प खुला है। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व गृहमंत्री भी इस बात से सहमत होंगे। ■

पृष्ठ 19 का शेष

तो साफ है कि सन् 2010 के जनसंख्या मापदंडों के आधार पर अस्पतालों एवं स्वास्थ्य केन्द्रों की वर्तमान आवश्यकता (सन् 2001 के आधार पर) से कई गुणा अधिक होगी।

हालात को देखते हुए केन्द्र सरकार को अपने इस दायित्व का निर्वाह स्वयं करना चाहिए और राज्य सरकारों को भी इस दिशा में पहल करने का निर्देश देना चाहिए। लेकिन हुआ उल्टा है। वर्ष 2010–11 के बजट में स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र को सरकारी आवंटन सकल घरेलू उत्पाद का 0.30 प्रतिशत है। अलबत्ता यह वर्ष 2009–10 बजट में आवंटित 0. 37 प्रतिशत से भी कम है। वित्त मंत्रीजी ने अपने 2010–11 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को 22,300 करोड़ रुपये आवंटित किया है, जो पिछले वर्ष के बजट आवंटन से 2,700 करोड़ रुपये मात्र अधिक है। अगर हम स्वास्थ्य क्षेत्र की आवश्यकताओं को देखें तो लगता है यह वृद्धि नाम मात्र की है।

स्वास्थ्य क्षेत्र के संदर्भ में हम जब विचार करते हैं तो देखने में आता है कि इस बजट में नए अस्पतालों के निर्माण की बात तक नहीं रखी गई है जबकि एक अनुमान के अनुसार आगामी कुछ वर्षों में देश में एक लाख से भी अधिक अस्पताल बैडों की आवश्यकता होगी। देश के शीर्ष मेडिकल कॉलेजों की जबरदस्त उपेक्षा हो रही है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (नई दिल्ली) को वर्ष 2010–11 के लिए मात्र 800 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है, जबकि वर्ष 2009–10 में 886.50 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था। नई दिल्ली स्थित सफदरगंज अस्पताल को वर्ष 2010–11 में 237 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है जबकि वर्ष 2009–10 में 284 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था।

सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों का वर्ष 2010–11 के लिए 982.10 करोड़ रुपये आबंटित किया गया है जबकि 2009–10 में 1020.33 करोड़ रुपये आवंटित किया गया था।

आखिर, ऐसे निर्णय को क्या समझा जाए और क्या कहा जाए? आबादी बढ़ रही है और स्वास्थ्य पर सरकार बजट कम कर रही है। ऐसे निर्णय को भला कौन आम आदमी के हित में कहेगा?

एक नजर हम इस ओर देखें। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 9 लाख भारतीय प्रतिवर्ष प्रदूषित जल पीने एवं प्रदूषित हवा लेने से मर जाते हैं। खुद हमारी सरकार कहती है कि देश में 55 प्रतिशत घरों में शौचालय नहीं है। भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में होने वाले व्यय में 80 प्रतिशत निजी व्यय है। ये व्यय संबंधित है बड़ी कंपनियों के स्टाफ पर खर्च, धनी भारतीयों द्वारा बेहतर निजी स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग। यह व्यय प्रत्यय/अप्रत्यक्ष रूप से देश की गरीब जनता के जेब से जाता है।

आप जानते ही होंगे कि 10 भारतीयों में से केवल एक के पास किसी प्रकार का स्वास्थ्य बीमा है। कुल स्वास्थ्य व्यय का 86.4 प्रतिशत लोगों द्वारा स्वयं वहन किया जाता है।

यूपीए सरकार का यह दावा कि स्वास्थ्य क्षेत्र पर सरकारी व्यय में वर्तमान सकल उत्पाद का 1 प्रतिशत से बढ़ाकर 2010 तक 3 प्रतिशत कर दिया जाएगा। परन्तु वर्ष 2010–11 का बजट स्वयं केन्द्र सरकार की पोल खोल रहा है। यूपीए सरकार को चाहिए कि वह रामचरितमानस के नीतिमूलक पाठ को पढ़े और उस पर अमल करे।

तुलसीदास ने कहा है–

"जासू राज प्रिय प्रजा दुखारी।
सो नृप अवसि नरक अधिकारी।।■

(लेखक भाजपा के सांसद व पूर्व राष्ट्रीय सचिव हैं)

यूपीए मंत्री का आचरण आपराधिक अनाचार के समान : रविशंकर प्रसाद

Hkkरतीय जनता पार्टी का बीसीसीआई या आईपीएल के आन्तरिक प्रबंधन से कोई लेना–देना नहीं है। भाजपा का आईपीएल फ्रेंचाइज़ और आईपीएल कमिश्नर द्वारा दिए गए बयानों से भी कुछ लेना–देना नहीं है। ये क्रिकेट संस्था के आन्तरिक मामले हैं, जिन पर एक राजनीतिक दल होने के नाते हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे।

भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार के एक मंत्री के आचरण पर निश्चित रूप से चिंतित है। हाल के घटनाक्रम ने दर्शाया है कि श्री शशि थरूर इस सरकार के enfant terrible है। उनका आचरण ऐसा रहा है, जो एक यूनियन मिनिस्टर के लिए शोभनीय नहीं है। जहां उनके पहले के बयानों ने राजनीतिक अपरिपक्वता का परिचय दिया था, वहीं किसी फ्रैचाइज़ विशेष – Randezvous Sports World का जहां तक संबंध है उसमें उनकी रूचि दर्शाना ऐसा आचरण है, जो एक यूनियन मिनिस्टर को शोभा नहीं देता है। शशि थरूर का यह बयान है कि उन्होंने क्रिकेट को केरल में लाने के लिए केवल कोच्चि फ्रेंचाइज़ की सहायता की है। हमें केरल में क्रिकेट को लाने के उनक प्रयासों पर कोई आपत्ति नहीं है। यदि उनका केरल के प्रति प्यार था या क्रिकेट को केरल में लाने की इच्छा थी जिसने उनको कोच्चि फ्रेंचाइज़ की मदद करने के लिए प्रेरित किया तब भाजपा को कोई आपत्ति नहीं होती। किंतु सत्य अन्यथा प्रतीत होता है। यह इस कदम से वाणिज्यिक लाभ उठाने की इच्छा ही थी, जिसने उन्हें इस मामले में दखलंदाजी करने के लिए उकसाया। निम्नलिखित तथ्य स्वतः स्पष्ट है :

- शशि थरूर ने यह स्वीकार किया है कि उन्होंने कोच्चि फ्रेंचाइज़ की कई बार सहायता की।
- कोच्चि फ्रेंचाइज़ ने आईपीएल को जानकारी दे दी थी कि सुश्री सुनंदा पुष्कर के पक्ष में स्वीट इक्वीटी अर्थात् फ्री इक्वीटी स्टेक जारी किया गया है।
- हालांकि भाजपा की शशि थरूर के वैयक्तिक मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं है, फिर भी रिपोर्टों के अनुसार सुनंदा पुष्कर के शशि थरूर से निकट के संबंध है। सुनंदा पुष्कर ने माना है कि उन्होंने क्रिकेट की या केरल की या कोच्चि फ्रेंचाइज़ की ऐसी कोई सेवा नहीं की है जो उन्हें उक्त कंपनी में फ्री इक्वीटी का अबाध हकदार बना सकती हो। स्पष्ट है कि इस इक्वीटी के वास्ते quid pro quo शशि थरूर द्वारा कोच्चि फ्रेंचाइज़ को दी गई सेवा ही है।
- यह स्पष्ट है कि शशि थरूर ने कोच्चि फ्रेंचाइज़ को दी गई सेवा के वास्ते प्रतिफल प्राप्त किया है और वह प्रतिफल किसी के नाम में लिए गए मूल्यवान शेयर होल्डिंग हैं, जिनका उनका निकट का संबंध है।

यह सरासर अस्वीकार्य है कि केन्द्रीय सरकार के किसी मंत्री को ऐसे आचरण में लिप्त होना चाहिए। भारत के प्रधानमंत्री ऐसे आचरण को कैसे नजरंदाज कर सकते हैं।

शशि थरूर ने एक चालाकी भरे शब्दों में इसका खंडन जारी किया है, जिसमें पूरी सच्चाई को छिपाया गया है। जबकि वे यह कहते है कि उन्होंने कोच्चि फ्रेंचाइज में एक भी रूपया न तो निवेश किया है और न ही प्राप्त

गत अप्रैल 13, 2010 को भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव एवं मुख्य राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रवि शंकर प्रसाद द्वारा जारी प्रेस वक्तव्य

किया है। माना कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है किन्तु उनके निकट सहयोगियों ने बिना भुगतान किए शेयर प्राप्त किए है। जब उसके साथ निकटता साथ रखने वाला व्यक्ति शेयर होल्डिंग प्राप्त करता है तब क्या वे इस बात से इनकार कर सकते है कि उनसे उन्हें लाभ प्राप्त नहीं होगा जबकि वो फ्री इक्वीटी है।

ऐसा आचरण अनुचित होने के साथ–साथ एक दांडिक अपराध है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13 आपराधिक आचरण को परिभाषित करती है जबकि कोई सार्वजनिक सेवक अपने पद का या सार्वजनिक सेवा को दुरूपयोग करता है और अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या वित्तीय लाभ प्राप्त करता है।

शशि थरूर ने 'किसी अन्य व्यक्ति' के नाम में कोई मूल्यवान वस्तु या वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए कोच्चि फ्रेंचाइज़ के मामले को आगे बढ़ाने में मंत्री के रूप में अपने पद का दुरूपयोग किया है। उक्त अधिनियम की धारा 20 के तहत सार्वजनिक सेवक द्वारा अपने नाम में या किसी अन्य व्यक्ति के नाम में विधिपूर्ण पारिश्रमिक के अलावा अन्य अनुतोष प्राप्त किया जाना एक आपराधिक आचरण की विधिक धारणा का सृजन करता है।

भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट मत है कि शशि थरूर के मंत्री के रूप में किए गए अनौचित्य के बाद उनको एक क्षण के लिए भी सरकार में बनाए नहीं रखा जा सकता। उनका आचरण आपराधिक अनाचार के समान है, जो कानून में दंडनीय अपराध है। प्रधानमंत्री को उन्हें तत्काल सरकार से बर्खास्त कर देना चाहिए और इस केस को आपराधिक अन्वेषण के लिए सीबीआई को निर्दिष्ट कर देना चाहिए। ■

सरकार की शह पर सड़ाया जा रहा अनाज : नितिन गडकरी

Hkkरतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी का मानना है कि सरकार की शह पर गोदामों में जानबूझकर अनाज सड़ाने का कुचक्र रचा जाता है , ताकि सड़े हुए अनाज को शराब बनाने के लिए

भेजा जा सके। श्री गडकरी मुंबई में पत्रकारों से बात कर रहे थे।

दिल्ली में होने जा रही महंगाई विरोधी रैली की तैयारियों के सिलसिले में मुंबई पहुंचे श्री नितिन गडकरी ने यहां पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन देकर पत्रकारों को बताया कि किस तरह केंद्र की यूपीए सरकार महंगाई के मुद्दे पर जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। देश के कई हिस्सों का दौरा करके महाराष्ट्र पहुंचे गडकरी के अनुसार पंजाब एवं उत्तर भारत में गोदामों की कमी के चलते किसानों का 40 प्रतिशत गेहूं अभी खुले आसमान के नीचे पड़ा है। मौसम विभाग का हवाला देते हुए गडकरी ने कहा कि यदि आनेवाले सप्ताह में उत्तर भारत में बारिश की झोंका आ गया तो यह सारा गेहूं सड़ने के कगार पर पहुंच जाएगा। इससे जहां एक ओर किसानों का नुकसान होगा, वहीं महंगाई और बढ़ेगी।

पत्रकार वार्ता में सड़े हुए गेहूं के नमूने लेकर आए गडकरी ने सरकार पर आरोप लगाया कि सरकारी मदद से गोदामों में अनाज सड़ाने का एक बड़ा रैकेट चल रहा है, ताकि सड़ा हुआ अनाज शराब बनाने के काम आ सके। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बढ़ती महंगाई के लिए केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार से ज्यादा जिम्मेदार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह एवं यूपीए सरकार की नीतियों को बताया। गडकरी के अनुसार अर्थशास्त्र के ज्ञाता प्रधानमंत्री ने पिछले लोकसभा चुनाव से पहले देश से वादा किया था कि दुबारा यूपीए सरकार बनी तो सौ दिन में महंगाई दूर कर ली जाएगी, जबकि अब यूपीए सरकार के एक साल पूरे होने जा रहे हैं और महंगाई साल भर पहले की तुलना में सौ प्रतिशत तक बढ़ गई है। गडकरी ने उम्मीद जताई कि दिल्ली में बढ़ते पारे के बावजूद बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता 21 अप्रैल को महंगाई के विरोध में संसद का घेराव करने दिल्ली पहुंचेंगे।■

सरकारी गोदामों में सड़ रहे हैं अनाज - राजनाथ सिंह

सड़े-गले और अखाद्य गेहूं को तुरंत नष्ट करें

हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब में भारतीय खाद्य निगम के खुले वेयर–हाउसों में 72 लाख टन गेहूं पड़ा हुआ है। इसमें से भारी मात्रा सड़–गल गई है। यह गेहूं एक साल से भी अधिक समय से वहां अनारक्षित पड़ा हुआ है। इस आपराधिक उपेक्षा के परिणामस्वरूप गेहूं की यह मात्रा उपभोग के अयोग्य हो गई है।

गत 16 अप्रैल, 2010 को भाजपा के वरिष्ठ नेता श्री राजनाथ सिंह ने अपने साथ राष्ट्रीय सचिव डॉ. किरीट सोमैय्या, हरियाणा राज्य के भाजपा अध्यक्ष श्री किशनपाल गूजर को साथ लेकर हरियाणा के विभिन्न भागों में स्थित कई खुले वेयर–हाउसों का अचानक दौरा किया। खुले वेयर–हाउसों ने पड़े हुए गेहूं की हालत देखकर इस टीम को भारी धक्का लगा। पलवल जिले के भगोला में 2 लाख से भी अधिक गेहूं की बोरियां एक वर्ष से अधिक अवधि से खुले में पड़ा हुआ है। आलापुर, फिराज़पुर में सबसे बुरी हालत देखने में आई। यहां 2 लाख गेहूं की बोरियां एक वर्ष से अधिक अवधि से खुले में पड़ी हुई हैं।

	WHEAT	RICE	TOTAL Lakh Ton
BUFFER NORMS	82	118	200
ACTUAL STOCKS	183.88	269.50	453.38

श्री राजनाथ सिंह ने स्वयं इनमें से प्रत्येक गोदाम से सैम्पल इकट्ठे किए।

सौंध, हथीन और अन्य क्षेत्रों से अन्य खुले वेयर–हाउसों से भी सैम्पल इकट्ठे किए गए। वहां भी गेहूं इसी तरह संक्रमित और सड़ा–गला पाया गया। 3.5 लाख बोरियां हथीन और सौंध में पड़ी हुई हैं।

भारतीय खाद्य निगम के केन्द्रीय पूल में 183 लाख टन गेहूं जमा है। भारत सरकार ने माना है कि 80 लाख मीट्रिक टन से भी अधिक गेहूं खुले गोदामों में पड़ा है।

खाद्यान्न के 200 लाख टन के बफर स्टॉक मानक के विरूद्ध सरकार के पास खाद्यान्न का 453.38 लाख टन खाद्यान्न जमा है। सरकार के पास गेहूं आधिक्य में जमा है।

कुप्रबंधन और हेर–फेर के कारण सरकार के पास पड़ी खाद्यान्न की भारी मात्रा सड़ रही है। गरीबों और जरूरतमंदों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। सक्सेना समिति के अनुसार 51 प्रतिशत पात्र गरीबों को बीपीएल कार्ड नहीं मिले हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए दी जाने वाली खाद्यान्न की मात्रा 35 किलो से घटाकर 25 किलो कर दी गई है।

श्री राजनाथ सिंह इन सैम्पलों को लोकसभा के माननीय अध्यक्ष को प्रस्तुत करेंगे और सोमवार 19 अप्रैल, 2010 को संसद सत्र में उठाएंगे। उनकी मांग है :

1. खुले वेयर–हाउसों का दौरा करने के लिए एक संसदीय समिति गठित की जाए।
2. समिति को निम्नलिखित की जांच करनी चाहिए :

(क) गोदामों में खुले में पड़े गेहूं की स्थिति
(ख) खुले गोदामों में स्टॉक रखने का कारण
(ग) इस स्टॉक को अन्य गेहूं में क्यों और कैसे मिलाया जाता है तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरित किया जाता है।
(घ) गले–सड़े गेहूं का निपटान
(ड़) ऐसे वेयर–हाउसों में गेहूं की इतनी बड़ी मात्रा क्यों भंडारित की गई और गरीबों में क्यों वितरित नहीं की गई और
(च) ऐस कुप्रबंधन तथा हेर–फेर के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की पहचान करना

श्री राजनाथ सिंह ने चिंता व्यक्त की कि एक ओर सरकारी गोदामों में लाखों टन खाद्यान्न सड़ रहा है और दूसरी ओर लोग भूख से मर रहे हैं। कांग्रेस सरकार को इस गैर–जिम्मेवाराना और भ्रष्ट व्यवहार के लिए स्पष्टीकरण देना चाहिए। ■

[FIG.IN MT]

REGION	QTY.IN CAP		
	FCI	STATE AGENCIES	TOTAL
PUNJAB	48,226	41,57,486	42,05,712
HARYANA	59,559	24,85,351	25,44,910
RAJASTHAN	3,87,160	0	3.87,160
UTTAR PRADESH	98,453	0	98,453
TOTAL	5,93,398	66,42,837	72,36,235

रंगनाथ मिश्रा आयोग रिपोर्ट संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन

lokknnkrk }kjk

रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट का ड्राफ्ट जिसपर आयोग में आमसहमति बनी थी क्या उसे बदल दिया गया और इसके सदस्य सचिव श्रीमती आशा दास की जानकारी के बगैर ही दूसरी रिपोर्ट को छपने के लिए भेज दिया गया? यह प्रश्न राजधानी दिल्ली में भारत नीति प्रतिष्ठान द्वारा आयोजित "रंगनाथ मिश्रा आयोग के दुष्परिणाम" विषय पर संगोष्ठी में उठाया गया। संगोष्ठी की मुख्य वक्ता आशा दास से इसका स्पष्टीकरण मांगा गया। श्रीमती दास ने अपने भाषण में कहा कि इस प्रश्न में उन्हें असमंजस मे डाल दिया है। उनके अनुसार शुरु में आयोग के सदस्यों का सहयोग था बाद में लामबंदी हो गयी और बाद के अध्यायों में जिनबातों पर सहमति बनी थी उसे बदल दिया गया। आयोग के ऊपर यह एक गंभीर आरोप लगाया गया है, जो इसकी कार्यपद्धति पर प्रश्न खड़ा करता है। प्रतिष्ठान के मानद निदेशक प्रो॰ राकेश सिन्हा ने इस बात पर भी स्पष्टीकरण चाहा कि आयोग के अंतिम बैठक में आशा दास को नहीं बुलाया गया और जो रिपोर्ट छपने के लिए गई उस पर उनके हस्ताक्षर नही थे।

आशा दास ने रिपोर्ट को संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के आदेश 1950 के अंतर्गत दलित मुस्लिमों एवं दलित ईसाइयों को शामिल करना एक गलत कदम होगा। उन्होंने बौद्धों एवं सिखों को इसके अन्तर्गत लाने को गलत करार दिया। आशा दास की यह बात उनके द्वारा अपनी आयोग की रिपोर्ट की असहमति पत्र में लिखी बात से भिन्न है। उसमें इसे उन्होंने जायज ठहराया था। उन्होने कहा कि पहली गलती आगे की गलती का आधार नहीं हो सकता है।

उन्होंने आरिफ मोहम्मद खान, जो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे, उनकी यह तर्क कि "इस्लाम में जाति प्रथा है" का जोरदार खण्डन करते हुए कहा कि आयोग को मुस्लिम संगठनों एवं बुद्धिजीवियों से जो मेमोरेंडम दिया गया उसमें मुस्लिमों में जातिवाद या छुआछूत नहीं होने की बात कही गई है। आशा दास ने कहा कि रिपोर्ट के प्रति असहमति जताना उनके अधिकार क्षेत्र में था और ऐसा करना इसलिए जरुरी था कि आरम्भ में जो व्यापक मापदंड के आधार पर आयोग ने काम शुरु किया था उसकी बाद में तिलांजलि दे दी गयी।

> ***अनुसूचित जातियों के सम्बन्ध में राष्ट्रपति के आदेश 1950 के अंतर्गत दलित मुस्लिमों एवं दलित ईसाइयों को शामिल करना एक गलत कदम होगा। बौद्धों एवं सिखों को इसके अन्तर्गत लाना भी उचित नहीं है।***

पूर्व केन्द्रीयमंत्री आरिफ मोहम्मद खान ने धर्म के आधार पर आरक्षण को पूरी तरह से असंवैधानिक एवं राष्ट्रविरोधी घोषित किया। उनके अनुसार सभी प्रकार के अलगाववाद का विरोध किया जाना चाहिए। उनके मतानुसार रंगनाथ मिश्रा आयोग की रिपोर्ट देश को लखनऊ पैक्ट 1916 के समय में वापस लेजाना चाहता है। इसका किसी भी कीमत पर समर्थन नहीं किया जाना चाहिए।

विवेक साप्ताहिक (मुंबई) के प्रधान संपादक श्री रमेश पतंगे ने कहा कि वर्त्तमान सरकार अल्पसंख्यकों का अल्पसंख्यकों द्वारा एवं अल्पसंख्यकों के लिए है। उन्होंने कहा कि रंगनाथ मिश्रा रिपोर्ट अनुसूचित जातियों के हिस्से को कथित अल्पसंख्यकों को भेंट चढ़ाना चाहती है। कार्यक्रम का संचालन करते हुए प्रो. राकेश सिन्हा ने कहा कि सच्चर कमेटी ने रंगनाथ मिश्रा कमीशन की पृष्ठभूमि तैयार की थी। वर्त्तमान राजनीति अल्पसंख्यक केंद्रित होती जा रही है। उन्होंने प्रश्न किया कि रंगनाथ मिश्रा आयोग ने अल्पसंख्यक अवधारणा को परिभाषित करते समय न तो संविधान सभा की बहस को न ही प्रगतिशील मुस्लिम बुद्धिजीवियों यथा ए.ए.ए.फैजी, हुमायूं कबीर, एम.एच.बेग, एम.आर ए.बेग, मोइन शकीर को उद्धृत किया है? सभा में बड़ी संख्या में शिक्षक, छात्र, राजनेता एवं पत्रकार उपस्थित थे। भारत नीति प्रतिष्ठान में इस विषय पर तीन बैठकें पहले हो चुकी हैं। ■